सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मई 2021 | अंक 02

ध्येयIAS
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मई 2021 | अंक 02

विषय सूची

- सप्ताह के प्रमुख मुद्दे — 1-13
- सप्ताह के चर्चित व्यक्ति — 14-18
- सप्ताह के चर्चित स्थान — 19-22
- सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस — 23-26
- ब्रेन बूस्टर — 27-34
- स्वयं को जाँचें (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) — 35-40
- स्वयं को जाँचें (विषयनिष्ठ प्रश्न) — 41-42

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	कुरबान अली
प्रबंध संपादक	आशुतोष सिंह
संपादक	जीत सिंह अवनीश पाण्डेय ओमवीर सिंह चौधरी
मुख्य लेखक	अजय सिंह अहमद अली स्नेहा तिवारी
लेखक	अशरफ अली गिरराज सिंह हरिओम सिंह अंशुमान तिवारी
समीक्षक	रंजीत सिंह रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	संजीव कुमार झा पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	गुफरान खान राहुल कुमार
प्रारूपक	कृष्ण कुमार कृष्णकांत मंडल मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	हरीराम राजू यादव

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 'विभाजन रेखा'

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक
- मालदीव के निकट गिरा 'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई 2' रॉकेट
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज
- मराठा आरक्षण असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- डबल्यूटीओ में पेटेंट संबंधी सुरक्षा से छूट का प्रस्ताव
- 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज, आयुष-64 और काबासुरा कुडिनीर मेडिसिन
- 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021: वन ईयर ऑफ कोविड-19' रिपोर्ट
- ब्लैक फंगस
- भारत में 5G इंटरनेट तकनीक का ट्रायल
- तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया
- खाद्य मूल्य सूचकांक वर्ष 2014 के बाद से उच्चतम स्तर पर
- वैश्विक मीथेन आकलन
- स्पेसएक्स डॉग -1 मिशन टू द मून
- बेन्नू क्षुद्रग्रह (Bennu asteroid) और ओसीरिस-रेक्स अंतरिक्षयान (OSIRIS-REx Spacecraft)

सामान्य अध्ययन-1

भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज

1. माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 'विभाजन रेखा'

चर्चा का कारण

- हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चीन द्वारा 'एक विभाजन रेखा' बनाने की योजना बनाई जा रही है।

विभाजन रेखा खीचने के कारण क्या हैं?

- कोरोनावायरस के संचरण को रोकने के लिए, चीन नेपाल (जहां वर्तमान में कोरोना महामारी की लहर बढ़ रही है।) से चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के साथ घुलने-मिलने से रोकने के लिए शीर्ष पर एक 'विभाजन रेखा' बनाने की योजना बना रहा है।
- एवरेस्ट चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है और इस पर दोनों ओर से पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं। दिसंबर में, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से समुद्र तल से 8,848.86 मीटर ऊपर पहाड़ की 'नई' ऊंचाई की घोषणा की थी - जो कि भारतीय सर्वेक्षण द्वारा 1954 के बाद से मान्यता प्राप्त 86 सेमी अधिक है। एवरेस्ट के शिखर पर भारी बर्फ रहती है और एक समय पर केवल 6 लोग ही वहाँ खड़े हो सकते हैं, जिस समय अधिक पर्वतारोही रास्ते में होते हैं तो वहाँ लाइन लग जाती है।

मुख्य बिन्दु

- नेपाल जिसकी अधिकतर आय एवरेस्ट के अभियानों पर निर्भर करती है, उसने इस समय 400 विदेशी पर्वतारोहियों को अनुमति दी हुई है।
- नेपाल में इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और हालिया हफ्तों में

नेपाल की तरफ से चढ़ाई करने वाले 30 से अधिक बीमार पर्वतारोहियों को बचाया गया है।
- इसके अलावा नेपाल सीमा के किनारे एवरेस्ट बेस कैंप में भी कोविड-19 मामलों का पता चला है।
- नेपाल में इस समय 3,94,667 से अधिक कोरोना के मामलों की पुष्टि हो चुकी है जबकि इसके कारण 3,720 लोगों की मौत हुई है।
- नेपाल, जिसका पर्यटन क्षेत्र वैश्विक महामारी संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, ने अब तक वसंत चढ़ाई के मौसम को रद्द नहीं किया है, जो मानसून की बारिश शुरू होने से पहले अप्रैल से जून तक रहता है।
- वर्तमान में बिना अनुमति के अभी पर्यटकों को चीन के बेस कैम्प में जाने की अनुमति नहीं है। चीन ने विदेशी लोगों के पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।
- चीन में स्थिति बिल्कुल अलग है, जहां महामारी को काफी हद तक दबा दिया गया है।
- चीन ने अपनी ओर से महामारी की शुरुआत के बाद से किसी भी विदेशी पर्यटक को पहाड़ पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी है।
- चीन की ओर से चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को नेपाल की ओर से आने वाले किसी भी शख्स से संपर्क करने से प्रतिबंधित किया गया है और शिखर पर रखी हुई चीजों को भी छूने की अनुमति नहीं दी गई है।
- तिब्बत के स्पोर्ट्स ब्यूरो के डायरेक्टर ने चीन के सरकारी मीडिया से कहा है कि उत्तर और दक्षिण की ओर से चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही केवल एवरेस्ट के शिखर पर ही एक-दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं।
- चीन के अनुसार, तिब्बती चढ़ाई करने वाले गाइडों की एक छोटी टीम एवरेस्ट पर चढ़ेगी और चोटी के दोनों ओर से पर्वतारोहियों के बीच किसी भी संपर्क को रोकने के लिए शिखर पर "विभाजन की रेखा" स्थापित करेगी, लेकिन यह नहीं बताया कि यह कैसे करेगी। 21 चीनी नागरिकों का एक समूह वर्तमान में तिब्बत की ओर शिखर सम्मेलन के रास्ते में है। यह अभी तक साफ नहीं है कि इन प्रतिबंधों को बरकरार रखने के लिए तिब्बती गाइड इस इलाके में कब तक रहेंगे।

सामान्य अध्ययन-2

शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत ने 'तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय' (3rd Arctic Science Ministerial-ASM3) बैठक में भाग लिया है।

प्रमुख बिन्दु

- इस बैठक में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विभिन्न हितधारकों के साथ आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य और सहयोग के लिए भारत के दृष्टिकोण और दीर्घकालिक योजनाओं को साझा किया।
- डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भारत अवलोकन, अनुसंधान, क्षमता निर्माण के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु संकल्पबद्ध है। इसके लिए भारत आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में गूढ़ जानकारी को साझा करने में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा।
- इसके अलावा, भारत ने आर्कटिक क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग की अपनी योजना भी साझा की।
- डॉ हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि सस्टेनेबल आर्कटिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क (एसएओएन) में भारत का योगदान जारी रहेगा।
- उल्लेखनीय है कि 'तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय' (3rd Arctic Science Ministerial-ASM3) बैठक का आयोजन आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस वर्ष का विषय 'नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक' है।
- पहली दो बैठकों एएसएम1 और एएसएम 2 का क्रमशः यूएसए (वर्ष 2016) और जर्मनी (वर्ष 2018) में आयोजन किया गया था।
- 'आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय' बैठकें, आर्कटिक परिषद में शामिल सदस्य देशों द्वारा की जाती हैं।

नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह मिशन के बारे में

- भारत और यूएसए के सहयोग से एनआईएसईआर (नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार) उपग्रह मिशन का शुभारंभ हो रहा है। एनआईएसआर का उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह के परिवर्तनों के कारण और परिणामों का वैश्विक रूप से मापन करना है।

आर्कटिक परिषद के बारे में

- आर्कटिक परिषद में आर्कटिक क्षेत्र के आस-पास के देश शामिल हैं। आर्कटिक परिषद में सदस्य राज्य के रूप में आठ परिध्रुवीय देश निम्नलिखित हैं- कनाडा, डेन्मार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन तथा अमेरिका।
- आर्कटिक परिषद की स्थापना वर्ष 1996 में 'ओटावा घोषणा' से हुई थी।
- भारत को वर्ष 2013 से आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है।
- भारत के अलावा आर्कटिक परिषद के अन्य पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं - जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया।
- आर्कटिक परिषद, आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग, समन्वय और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च-स्तरीय अंतर शासकीय फोरम है।

भारत और आर्कटिक क्षेत्र

- फ्रांस के पेरिस में 'स्वालबार्ड संधि' पर हस्ताक्षर के साथ, आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ाव वर्ष 1920 से ही है।
- वर्ष 2008 के बाद से, भारत के पास आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्वे के स्वालबार्ड क्षेत्र के न्यालेसुंड में हिमाद्री नामक एक स्थायी अनुसंधान स्टेशन है।
- भारत से आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान का समन्वयन, संचालन और प्रचार-प्रसार भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) द्वारा किया जाता है।

2. मालदीव के निकट गिरा 'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई2' रॉकेट

चर्चा का कारण

- हाल ही में हिन्द महासागर में स्थित मालदीव के निकट 'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई2' (Long March-5B Y2) रॉकेट का मलबा गिरा है।

'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई2' के बारे में

- 'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई2' (Long March-5B Y2), एक चीनी रॉकेट है।
- इस रॉकेट का उपयोग चीन, अन्तरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन के निर्माण हेतु कर रहा है।
- 'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई2' रॉकेट, हाल ही में चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण हेतु तीन प्रमुख घटकों में से प्रथम घटक 'तियान्हे मॉड्यूल' (Tianhe module) को लेकर गया था।
- हालांकि 'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई2' रॉकेट अपने मार्ग से अनियंत्रित हो गया था और चीन के कंट्रोल से बाहर हो गया था। यही कारण है कि इस रॉकेट का मलबा मालदीव के उत्तर में हिंद महासागर में गिरा है।
- यह भी दावा किया जा रहा है कि इस विशालकाय रॉकेट का मलबा भारत तक देखा गया है। भारत में भी कई लोगों ने इस रॉकेट को आकाश में गिरते देखने का दावा किया है।

नासा द्वारा आलोचना

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने 'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई2' रॉकेट के मलबे का मालदीव के उत्तर में हिंद महासागर में गिरने को लेकर चीन की आलोचना की है। अमेरिका ने इसे चीन की गैरजिम्मेदारपूर्ण कारवाई कहा है। अमेरिका का कहना है कि इस तरह की घटनाएँ मानवता के लिए काफी खतरनाक हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि चीन मलबे को लेकर मानकों का पालन करने में असफल रहा है। नासा ने जोर देकर कहा कि यह जरूरी है कि चीन और अन्य देश अंतरिक्ष में 'जिम्मेदारी और पारदर्शिता' के साथ काम करें। इसके साथ ही अंतरिक्ष में इन अभियानों को लेकर विभिन्न देशों की अन्तरिक्ष एजेंसियों को और ज्यादा पारदर्शिता बरतनी चाहिए।

चीनी अंतरिक्ष स्टेशन

- चीन अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर रहा है। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम 'तियांगॉन्ग' (Tiangong) है। चीन ने तियांगॉन्ग (Tiangong) स्पेस स्टेशन के निर्माण कार्य के पूरा करने का लक्ष्य अगले साल के अंत तक रखा है। तियांगॉन्ग (Tiangong), का जीवनकाल 10 वर्ष का होगा, अर्थात यह वर्ष 2037 तक कार्य करेगा। उल्लेखनीय है कि तियांगॉन्ग, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बाद दुनिया का दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन होगा।

मालदीव

- मालदीव, हिन्द महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। दरअसल यहाँ प्रवाल द्वीप पाये जाते हैं, इसलिए यह देश पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। मालदीव, जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव की राजधानी माले है।

3. सोशल स्टॉक एक्सचेंज

चर्चा का कारण

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की एक तकनीकी समिति ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (social stock exchange) पर सामाजिक उद्यमों और गैर-लाभकारी संगठनों को शेयर सूचीबद्ध कराने के विस्तृत नियम बनाने के सुझाव दिए हैं। गौरतलब है कि सेबी ने नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष भानवाला की अध्यक्षता में सितंबर में तकनीकी समूह की स्थापना की थी।

पृष्ठभूमि

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2019-20 बजट भाषण में सोशल स्टॉक एक्सचेंजों के बारे में घोषणा की थी। सेबी ने इस घोषणा के बाद सितंबर 2019 में इशात हुसैन की अध्यक्षता में एक्सचेंजों पर एक कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजी) का गठन किया था। इसके बाद डब्ल्यूजी ने एसएसई पर सामाजिक उद्यमों की भागीदारी से संबंधित सिफारिशें कीं थी।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है?

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) स्टॉक एक्सचेंजों पर गैर-लाभकारी या गैर-सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है। इसके तहत यह उन्हें एक वैकल्पिक फंड जुटाने वाली संरचना प्रदान करता है। इसे बीएसई (BSE) या एनएसई (NSE) पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। यूके, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों में सोशल स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है।
- फंड जुटाने को कई उपकरणों के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है जैसे कि शून्य-कूपन-शून्य-प्रिंसिपल बॉन्ड, सामाजिक उद्यम निधि और म्यूचुअल फंड।

समिति के प्रमुख सुझाव

- समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कॉरपोरेट संस्थानों, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों तथा अन्य संस्थाओं को सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस समिति ने व्यावसायिक या व्यापार संघों और आवास कंपनियों को सोशल एक्सचेंज पर अनुमति नहीं देने की सिफारिश की है। हालांकि, उसने कहा कि किफायती आवास श्रेणी की कंपनियों को अनुमति दी जा सकती है।
- इस समिति ने रिपोर्ट में पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से संबंधित पहलुओं और विशेष रूप से सामाजिक लेखा परीक्षकों पर विचार करने की सिफारिश की।
- रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ने के लिए गैर-लाभकारी संगठन (एपीओ) और लाभ

के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यम (एफपीई) का मुख्य उद्देश्य सामाजिक होना चाहिए तथा उनका काम अभाव वाले क्षेत्रों और वंचितों के हित पर केंद्रित होना चाहिए।

पूंजी निर्माण के लिए सुझाव

- इस पैनल ने एनपीओ (non profit organizations- NPOs) और एफपीई (FPEs) के लिए फंड जुटाने के विभिन्न तरीकों की सिफारिश की है। एनपीओ को इक्विटी, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, विकास प्रभाव बॉन्ड, सामाजिक प्रभाव निधि के साथ-साथ निवेशक म्यूच्यूअल फंड के माध्यम से 100 प्रतिशत अनुदानित या दान से कोष जुटाने में सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज का विचार एक सराहनीय पहल है।
- इसके अतिरिक्त समिति ने एफपीई के लिये इक्विटी, ऋण, विकास प्रभाव बॉन्ड और सामाजिक उद्यम निधि के माध्यम से धन उगाहने की सिफारिश की है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध संस्थाओं को अपनी सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट को ष्रणनीतिक इरादे और नियोजन, दृष्टिकोण, प्रभाव स्कोर कार्डष् जैसे पहलुओं को कवर करना होगा।

योग्य गतिविधियों के लिए सुझाव

- समिति ने सामाजिक उद्यम (एसई) के स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ने के लिए मोटे तौर पर 15 क्षेत्रों में काम की शर्तों की सिफारिश की है। पैनल ने जिन 15 क्षेत्रों में काम की शर्त की शर्त रखने की सिफारिश की है उसमें भुखमरी, गरीबी, कुपोषण और असमानता का उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, शिक्षा, रोजगार और आजीविका का समर्थन करना, लैंगिक समानता, सशक्तिकरण और सामाजिक उद्यमों का समर्थन करना शामिल हैं।
- लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और LGBTQA+ समुदायों को बढ़ावा देना होगा।
- इसके अतिरिक्त सतत् और हरित शहरों के निर्माण के लिये स्लम क्षेत्र के विकास, किफायती आवास और इस प्रकार के अन्य हस्तक्षेपों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- वन और वन्य जीव संरक्षण को संबोधित करने की आवश्यकता है।

4. मराठा आरक्षण असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा का कारण

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है।

मराठा आरक्षण कानून क्या था?

- महाराष्ट्र एसईबीसी अधिनियम, 2018 नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता था।
- महाराष्ट्र में एक दशक से मांग हो रही थी कि मराठों को आरक्षण मिले। 2018 में इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दे दिया।
- जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है।
- जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए तीन जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि इस मामले में बड़ी बेंच बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद मामला 5 जजों की बेंच के पास गया।
- उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी जातियों को दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण से अलग दिए गए मराठा आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन हुआ जिसमें आरक्षण की सीमा अधिकतम 50 प्रतिशत ही रखने को कहा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मराठों को 50% से अधिक सीमा तक आरक्षण देने को उचित ठहराने वाली कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी। सामान्य शब्दों में कहें तो मराठा समुदाय एक प्रभावशाली अगड़ा समुदाय है, तथा राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल हैं। ऐसे में उसे 50% से अधिक सीमा तक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।
- संवैधानिक पीठ ने महाराष्ट्र एसईबीसी अधिनियम को उस हद तक रद्द कर दिया, जब उसने समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में रखा। पीठ ने नौकरी और शिक्षा में मराठों को दिए गए आरक्षण को रद्द किया।
- संवैधानिक पीठ ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में 9-जजों की बेंच के फैसले में निर्धारित आरक्षण पर 50% सीमा पर फिर से विचार की आवश्यकता नहीं है।

1992 का इंदिरा साहनी फैसला

- 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इस पर इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दी थी।
- इस केस में नौ जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित सीटों, स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया है, बल्कि किसी समुदाय को आरक्षण प्रदान करने हेतु अर्हता की कसौटी उसका "सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन" है।

102वां संविधान संशोधन अधिनियम,2018

- 102वें संविधान संशोधन अधिनियम,2018 के तहत 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करने की शक्तियाँ प्रदान की गयीं हैं।

सामान्य अध्ययन-3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा-प्रबंधन

1. डबल्यूटीओ में पेटेंट संबंधी सुरक्षा से छूट का प्रस्ताव

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा हटाने का समर्थन किया है।

मुख्य बिन्दु

- कुछ दिनों पूर्व भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में एक प्रस्ताव दिया था कि कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट संबंधी सुरक्षा हटा ली जाए; ताकि विभिन्न फॉर्मा कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर कोरोना वैक्सीन का भारी मात्रा में उत्पादन कर सकें।
- दरअसल वैश्विक स्वास्थ्य संकट और कोविड-19 महामारी से निपटने की जरूरत को देखते हुए भारत एवं दक्षिण अफ्रीका ने 2 अक्टूबर, 2020 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें कहा गया था कि विकासशील देशों के लिए टीकों और दवाओं की त्वरित एवं सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ट्रिप्स पर समझौते के मानदंडों में छूट दी जाए।
- भारत और अन्य समान सोच वाले देशों द्वारा सक्रिय प्रयासों के परिणामस्वरूप इस प्रस्ताव को 120 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।
- अतः आने वाले दिनों में एक सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण के साथ डब्ल्यूटीओ में इस छूट को जल्द ही मंजूरी दी जा सकती है।

पेटेंट में छूट से लाभ

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा के हटने से कई लाभ होने की संभावना है।
- इससे कोरोना वैक्सीन के निर्माण की गति तेज होगी और वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन त्वरित गति से बढ़ेगा।
- इससे कोरोना वैक्सीन के लिए परेशानी का सामना कर रहे गरीब देशों को टीका मिलने की एक बड़ी उम्मीद जगी है।
- यह छूट सस्ते कोविड-19 टीके और आवश्यक चिकित्सा उत्पादों के उत्पादन की गति को बढ़ाने एवं समय पर इनकी उपलब्धता को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

चुनौतियाँ

- किसी भी उत्पाद या सेवा में पेटेंट आदि की सुरक्षा नहीं मिलने से रिसर्च एवं डेवलपमेंट प्रभावित होता है। कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा के हटने की पहल का दुनिया की दिग्गज फॉर्मा कंपनियों ने विरोध किया है। दवा कंपनियों का तर्क है कि इस छूट से कोरोना वैक्सीन का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के पास टेक्नॉलॉजी नहीं है।

ट्रिप्स (Trips) के बारे में

- यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू पर बना एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य देश अपने आप ही इस समझौते में शामिल माने जाते हैं। यह बाध्यकारी समझौता 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ था। ट्रिप्स निम्नलिखित सात प्रकार की बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की चर्चा करता है:
  - प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा उससे सम्बन्धित अधिकार (Copyright And Related Rights)
  - ट्रेड मार्क (Trade Mark)
  - भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication)
  - औद्योगिक डिजाइन (Industrial Design)
  - पेटेंट (Patents)
  - इन्टीग्रेटेड सर्किट की डिजाईन
  - अप्रकाशित सूचना का संरक्षण या ट्रेड सीक्रेट (Trade Secret)

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी, 1995 को बहुआयामी व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर में तात्कालिक सदस्यों की सहमति से अस्तित्व में आया। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है। डबल्यूटीओ के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
  - व्यापार समझौतों को प्रशासित करना,
  - व्यापार प्रतिनिधियों के लिए फोरम की स्थापना करना,
  - व्यापार विवादों को सुलझाना,
  - व्यापार नीतियों की निगरानी करना,
  - खविकासशील देशों के लिए तकनीकी सहयोग व प्रशिक्षण देना तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करना।

2. 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज, आयुष-64 और काबासुरा कुडिनीर मेडिसिन

चर्चा का कारण

- हाल ही में डीजीसीआई ने डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड-19 महामारी की दवा '2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज' (2-deoxy-D-glucose) के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी साथ ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आयुष-64 और काबासुरा कुडिनीर (AYUSH 64 - Kabasura Kudineer) औषधियों के राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान शुरू किया है।

'2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज' (2-deoxy-D-glucose)

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज (आईएनएमएएस) द्वारा '2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी)' दवा का एक 'एंटी कोविड-19' चिकित्सकीय अनुप्रयोग विकसित किया गया है।
- इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज (आईएनएमएएस) ने यह कार्य 'डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज (डीआरएल), हैदराबाद' के सहयोग से किया है।
- नैदानिक परीक्षण परिणामों (Clinical trial results) से ज्ञात हुआ है कि यह मेडिसिन (2-डीजी) अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों की तेजी से रिकवरी में मदद करती है।
- इसके अलावा, यह बाहर से ऑक्सीजन देने पर निर्भरता को भी कम करती है। इसलिए यह दवा कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए काफी फायदेमंद है।
- यही कारण है कि डीजीसीआई ने '2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज' (2-deoxy-D-glucose) के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ताकि वर्तमान में कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटा जा सके।

'आयुष-64' (AYUSH-64) औषधि

- 'आयुष 64' दवा, सप्तपर्ण (Alstonia scholaris), कुटकी (Picrorhiza kurroa), चिरायता (Swertia chirata) एवं कुबेराक्ष (Caesalpinia crista) औषधियों से बनी है।
- यह व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर बनाई गयी है और सुरक्षित तथा प्रभावी आयुर्वेदिक दवा है।
- इस दवाई को लेने की सलाह आयुर्वेद एवं योग आधारित नेशनल क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल (National Clinical Management Protocol) द्वारा भी दी गयी है।
- उल्लेखनीय है कि 'आयुष 64' औषधि या दवा को आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद (CCRAS) द्वारा विकसित किया गया है।

'आयुष-64' (AYUSH-64) औषधि का क्लीनिकल परीक्षण

- कुछ दिनों पूर्व भारत सरकार के आयुष मंत्रालय तथा सीएसआईआर (CSIR) ने मध्यम कोविड-19 संक्रमण हेतु 'आयुष-64' (AYUSH-64) की प्रभावकारिता और इसके सुरक्षित होने का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक और गहन नैदानिक (क्लीनिकल) परीक्षण पूरा किया गया था।
- इस परीक्षण में पाया गया कि 'आयुष 64' दवा हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए लाभकारी है।
- इस प्रकार कोविड-19 महामारी के विश्वव्यापी कहर के बीच 'आयुष 64' दवा हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के रोगियों के लिए आशा की एक किरण के रूप में उभरी है।
- देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का मजबूती से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अपनी पॉली हर्बल औषधि (poly herbal Ayurvadic drugs) आयुष-64 और काबासूरा कुडिनीर के राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान शुरू किया है। इन औषधियाँ को कोविड-19 संक्रमित रोगियों (जो अस्पताल में भर्ती नहीं हैं) को राष्ट्रीय स्तर पर वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस अभियान में मुख्य सहयोगी के रूप में 'सेवा भारती' (Sewa Bharati) संस्था को भी जोड़ा गया है।

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस)

- केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences -CCRAS), भारत सरकार के आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी) के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य प्रतिपादित करने, उसमें समन्वय स्थापित करने, उनका विकास करने एवं उसे समुन्नत करने हेतु एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है।

'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (DCGI)

- 'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (Drug Controller General of India- DCGI), भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दरअसल डीजीसीआई, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization-CDSCO) का प्रमुख होता है। यह एक भारतीय दवा नियामक संस्था है। यह भारत में विभिन्न दवाओं और टीके आदि के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, डीसीजीआई भारत में दवाओं के विनिर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक भी निर्धारित करता है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defense Research and Development Organization) भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिये देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गयी थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी इक्यावन प्रयोगशालाएँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं।

3. 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021: वन ईयर ऑफ कोविड-19' रिपोर्ट

चर्चा का कारण

- हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी- सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट (बंगलुरु) द्वारा 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021: वन ईयर ऑफ कोविड-19' शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड 19 महामारी के कारण देश में बेरोजगारी में वृद्धि होने के साथ आय में गिरावट, असमानता और गरीबी में बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट में मार्च 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में एक वर्ष के भीतर रोजगार, आय, असमानता और गरीबी पर COVID-19 के प्रभाव को दर्शाया गया है।

Employment and income had not recovered to pre-pandemic levels even in late 2020

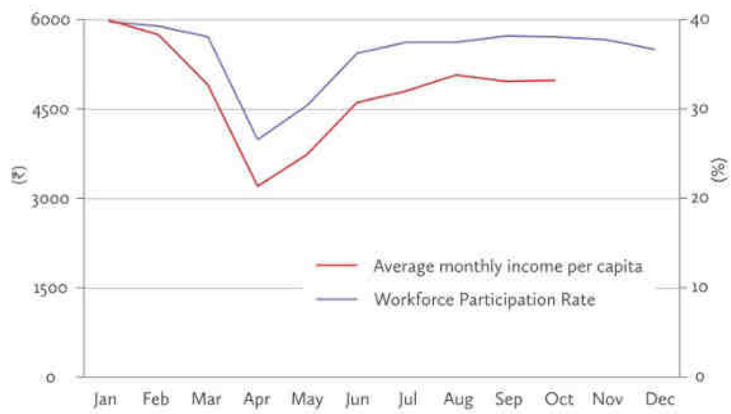

Sources and notes: Authors' calculations based on CMIE-CPHS. Incomes are in Jan 2020 prices and adjusted for seasonality.

रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु

- **कोविड 19 का रोजगार पर प्रभाव:** अप्रैल-मई 2020 के दौरान देश भर में 100 मिलियन नौकरियां चली गईं। हालांकि इनमें से अधिकांश श्रमिकों को जून 2020 तक रोजगार मिल गया था, किन्तु फिर भी लगभग 15 मिलियन कामगार वर्ष के अंत तक काम से वंचित रहे।
- रिपोर्ट के मुताबिक कोविड का सबसे ज्यादा असर युवा कामगारों पर पड़ा है। 15-24 वर्ष के आयु वर्ग में 33 फीसदी लोगों को दिसंबर 2020 तक रोजगार नहीं मिला जबकि 25 से 44 साल के बीच 6 फीसदी लोग रोजगार गंवा चुके थे।
- **आय में गिरावट:** चार सदस्यों के औसत परिवार वाले घरों के लिये अक्टूबर 2020 में प्रति व्यक्ति औसत मासिक घरेलू आय (4,979 रुपये) जनवरी 2020 की तुलना में अपने स्तर से नीचे (5,989 रुपये) थी।
- अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट की सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ी है। पिछले साल मार्च से अक्तूबर 2020 के बीच इससे 23 करोड़ गरीब मजदूरों की कमाई 375 रुपये की न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी इलाकों में गरीबी 20 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में 15 फीसदी तक बढ़ गई है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र में पलायन:** इस रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के पश्चात , लगभग आधे वेतनभोगी श्रमिक अनौपचारिक कार्यो में स्थानांतरित हो गए या फिर स्व-नियोजित (30%), आकस्मिक वेतन (10%) या अनौपचारिक वेतनभोगी (9%) कार्यों की ओर रुख किया । इस रिपोर्ट के अनुसार हाशिए पर पड़े कई लोगों ने मजबूरी में दैनिक मजदूरी के काम में कार्य करना शुरू कर दिया।
- **महिलाओं पर प्रभाव:** महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा लोगों की नौकरियां छूटीं। लॉकडाउन के दौरान और बाद के महीनों में, 61 प्रतिशत कामकाजी पुरुष कार्यरत रहे और 7 प्रतिशत ने रोजगार खो दिया और काम पर नहीं लौटे। महिलाओं के लिए, केवल 19 प्रतिशत ही कार्यरत रहीं और 47 प्रतिशत को लॉकडाउन के दौरान स्थायी नौकरी का नुकसान उठाना पड़ा और 2020 के अंत तक भी उनको रोजगार नहीं मिला।
- **गरीबी में बढ़ोतरी:** रिपोर्ट से पता चलता है कि महामारी ने अनौपचारिकता को और बढ़ा दिया है और अधिकांश श्रमिकों की कमाई में भारी गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप गरीबी में अचानक वृद्धि हुई है। महिलाएं और युवा कार्यकर्ता असंतुष्ट रूप से प्रभावित हुए हैं। संकट से प्रभावित कई परिवारों के लिए भोजन हासिल करना भी मुश्किल हो गया। इसका मुकाबला करने के लिए उनको उधार लेना पड़ा या परिसंपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकारी राहत ने संकट के सबसे गंभीर रूपों से बचने में मदद की , लेकिन समर्थन उपाय काफी साबित नहीं हुए।

रिपोर्ट के सुझाव

- अतिरिक्त सरकारी सहायता की अब दो कारणों से तत्काल आवश्यकता है- पहले वर्ष के दौरान हुए नुकसान की भरपाई और दूसरी लहर के प्रभाव की आशंका।
- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि 2021 के अंत तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाये।
- मनरेगा (महात्मा राष्ट्रीय गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम) का विस्तार किया जाना चाहिए और कार्यावधि को 150 दिनों के लिए बढ़ा देना चाहिए ताकि पात्र लोगों को लाभ हो।
- इसके अतिरिक्त 2.5 मिलियन आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्त्ताओं के लिये 30,000 रुपए का एक 'कोविड-19 कठिनाई भत्ता' (छह माह के लिये 5,000 रुपए प्रति माह) दिया जाना चाहिये।

4. ब्लैक फंगस

चर्चा का कारण

- हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोविड-19 से ठीक हो रहे लोगों में कवक (फंगल) संक्रमण के खतरे को लेकर सचेत किया है। 'म्यूकार माइकोसिस' नामक इस फंगल संक्रमण को सामान्य बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरोना से ठीक हो रहे या ठीक हो चुके लोगों को यह संक्रमण हो सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए यह संक्रमण खतरा बना हुआ है।

म्यूकर माइकोसिस क्या है?

- भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, म्यूकर माइकोसिस एक तरह का दुर्लभ फंगल इंफेक्शन है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलता है।
- यह संक्रमण मस्तिष्क, फेफड़े और त्वचा पर भी असर कर रहा है। इस बीमारी में कई के आंखों की रौशनी चली जाती है वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। अगर समय रहते इलाज न मिले तो मरीज की मौत हो सकती है।

पहले से बीमार लोगों को खतरा

- यह फंगल इंफेक्शन उन लोगों पर असर कर रहा है जो कोरोना की चपेट में आने से पहले ही किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त थे और उनका इलाज चल रहा था। इस कारण उनके शरीर की पर्यावरणीय रोगजनकों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।
- ऐसे लोग जब अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती होते हैं तो वहां के पर्यावरण में मौजूद फंगल उन्हें बहुत तेजी से संक्रमित करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाले स्टेरॉयड भी इस फंगल इंफेक्शन का कारण बन रहे हैं।

लक्षण

- इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खूनी उल्टी और बदली हुई मानसिक स्थिति के साथ आंखों या नाक के आसपास दर्द और लाली दिखना शामिल हैं।
- वहीं, स्किन पर ये इंफेक्शन होने से फुंसी या छाले पड़ सकते हैं और इंफेक्शन वाली जगह काली पड़ सकती है। कुछ मरीजों को आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना, पेट दर्द, उल्टी या मिचली भी महसूस होती है।
- यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है, जिसके चलते कई रोगी दृष्टिहीन हो गए हैं और इससे अन्य गंभीर दिक्कतें भी उत्पन्न हो रही हैं।

उपचार

- इसका इलाज एंटीफंगल के साथ किया जाता है लेकिन गंभीर स्थिति में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज को नियंत्रित करना, स्टेरॉयड का उपयोग कम करना और इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स को बंद करना सबसे महत्वपूर्ण हैं।
- इसके साथ ही शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना चाहिए।

5. भारत में 5G इंटरनेट तकनीक का ट्रायल

चर्चा का कारण

- दूरसंचार विभाग (DoT) ने 5जी नेटवर्क परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिन्दु

- दूरसंचार विभाग ने 5जी तकनीक के उपयोग के परीक्षण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली जिन कंपनियों को अनुमति दी,उनमें इसमें भारती एयरटेल, रिलाइंस जियोइंफोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन आईडिया इंडिया लिमिटेड और एमटीएनएल शामिल हैं।
- इन दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों ने एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी-डॉट जैसे मूल उपकरण विनिर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ करार किया है। जबकि रिलाइंस जियोइंफोकॉम लिमिटेड अपनी खुद की 5जी तकनीक का उपयोग करके यह परीक्षण करेगी।

परीक्षण के संदर्भ में

- दूरसंचार विभाग ने कहा है कि टेलिकॉम कंपनियों को 6 माह के लिए 5 जी स्पेक्ट्रम का ट्रायल करने की इजाजत दी जा रही है। इस अवधि में वे दो महीने भी शामिल होंगे, जिसमें इसके लिए जरूरी उपकरणों की खरीद और सेटिंग की जानी है।
- दूरसंचार कंपनियों को 5जी परिक्षण शहरी क्षेत्रों समेत ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी इलाकों में भी करना होगा ताकि 5जी तकनीक का लाभ केवल शहरों में ही नहीं बल्कि देशभर में उठाया जा सके।
- दूरसंचार कंपनियों (Telecom Service Providers - TSPs) को विभिन्न बैंडों में प्रायोगिक स्पेक्ट्रम प्रदान किये जाएंगे, जिसमें मिड-बैंड (3.2 गीगाहर्ट्ज से 3.67 गीगाहर्ट्ज), मिलीमीटर वेव बैंड (24.25 गीगाहर्ट्ज से 28.5 गीगाहर्ट्ज) और सब-गीगाहर्ट्ज बैंड (700 गीगाहर्ट्ज) शामिल हैं।
- 5G परीक्षणों के संचालन के उद्देश्यों में टेली-मेडिसिन, टेली-शिक्षा, ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियल्टी, ड्रोन-आधारित कृषि निगरानी जैसे अनुप्रयोग शामिल होंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) ने 5Gi तकनीक को भी मंजूरी दे दी है, जिसकी भारत द्वारा वकालत की गई थी, क्योंकि यह 5G टावरों और रेडियो नेटवर्क की बहुत

बड़ी पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। 5G तकनीक को IIT मद्रास, और आईआईटी हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है।

5G तकनीक

- 5G यानी पाँचवीं जनरेशन सेलुलर सेवा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसे 4G नेटवर्क का अगला वर्जन कहा जा सकता है। इसमें यूजर्स को ज्यादा नेट स्पीड, कम लेटेंसी और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। अब तक की सेलुलर टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी पर फोकस किया करती थी, लेकिन 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी एक कदम आगे बढ़ कर क्लाउड से क्लाइंट को सीधे कनेक्ट करेगा।
- इंटरनेट स्पीड की बात करें तो जाहिर है कि 5G की स्पीड 4G से काफी ज्यादा होगी। 4G की पीक स्पीड जहां 1 GBPS तक की है। वहीं, 5G की पीक स्पीड 20 GBPS यानी 20 जीबी प्रति सेकेंड तक की होगी। इससे कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर होने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी से हेल्थकेयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते खुलेंगे।
- विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले दिनों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, यातायात प्रबंधन, स्मार्ट सिटी के कई एप्लिकेशंस की एक विस्तृत शृंखला क्रांति की उम्मीद जताई जा रही है। डेटा रेट्स की बात करें तो जानकारों के मुताबिक, 5G तकनीकी में इसके 4G के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाने के आसार हैं।

6. तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया

चर्चा का कारण

- हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट (Glyphosate) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया दिया है। गौरतलब है कि ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है, जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है।

ग्लाइफोसेट

- ग्लाइफोसेट एक खरपतवारनाशी है। इसका IUPAC नाम N-(phosphonomethyl) Glycine है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1970 में शुरू किया गया था।
- फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि में बड़ी मात्रा इसका प्रयोग खूब किया जा रहा है। यह खरपतवारों को मारने के लिए पौधों की पत्तियों पर लगाया जाता है। नतीजतन पर्यावरण में ग्लाइफोसेट की मात्रा लगातार बढ़ रही है।
- 2015 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रेणी 2 ए के तहत ग्लाइफोसेट को वर्गीकृत किया, जो कि, "मानव में संभवत: कैंसरकारक" है।
- इस खरपतवारनाशक को सामान्य भाषा में 'राउंडअप' कहते हैं। इस राउंडअप को एक अमेरिकन कंपनी बनाती है।

तेलंगाना सरकार के कदम

- 2018 में, तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह हर्बिसाइड-सहिष्णु बीटी कपास के अवैध उपयोग को रोकने के लिए किया गया था। प्रतिबंधों के बावजूद, इसका उपयोग बंद नहीं हुआ।
- 2019 में, फिर से तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। प्रतिबंध लगाए जाने के कोई परिणाम नहीं होने के कारण, राज्य सरकार ने अब इस खरपतवार नाशक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत में ग्लाइफोसेट का प्रयोग

- भारत में ग्लाइफोसेट का प्रयोग पिछले दो दशकों में काफी बढ़ा है। पहले इसका प्रयोग सिर्फ असम तथा बंगाल के चाय बागानों में किया जाता था लेकिन अब इसका सर्वाधिक प्रयोग महाराष्ट्र में गन्ना, मक्का तथा फलों जैसे-अंगूर, केला, आम व संतरे को उगाने में किया जाता है।

ग्लाइफोसेट का पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव

- नदी के पारिस्थितिक तंत्र पर इस खरपतवारनाश का सबसे बुरा असर शैवालों की जैवविविधता पर पड़ता है। ग्लाइफोसेट के चलते पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है। शैवालों की अन्य प्रदूषण के कारकों का सामना करने की क्षमता भी लगातार खत्म होती जा रही है। यह राउंडअप फसल के उभोक्ता ही नहीं बल्कि उन किसानों को भी बीमार करता है जो इन फसलों को उगाते हैं। भारत में ऐसे कई मामले सामने भी आए।

7. खाद्य मूल्य सूचकांक वर्ष 2014 के बाद से उच्चतम स्तर पर

चर्चा का कारण

- खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation) के अनुसार अप्रैल, 2021 में लगातार 11वें महीने विश्व खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई। यह मई 2014 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। खाद्य कीमतों में वृद्धि खाद्य मूल्य सूचकांक (Food Price Index) के आधार पर की गई थी।

प्रमुख बिन्दु

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी के अनुसार वनस्पति तेल, मांस और डेयरी सूचकांकों में उछाल के कारण ये वृद्धि हुई है।
- अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पादों, मांस और चीनी के मासिक परिवर्तन को मापने वाले खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक मार्च महीने में औसतन 118.5 अंक रहा, जो फरवरी में थोड़ा बदलकर 116.1 अंक था।
- खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मार्च 2021 की तुलना में अप्रैल 2021 में अनाज के मूल्य सूचकांक में 2% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 26% की वृद्धि हुई है।
- डेयरी की कीमतों में 2% की वृद्धि हुई। दुग्ध उत्पाद जैसे दूध पाउडर, मक्खन, पनीर की

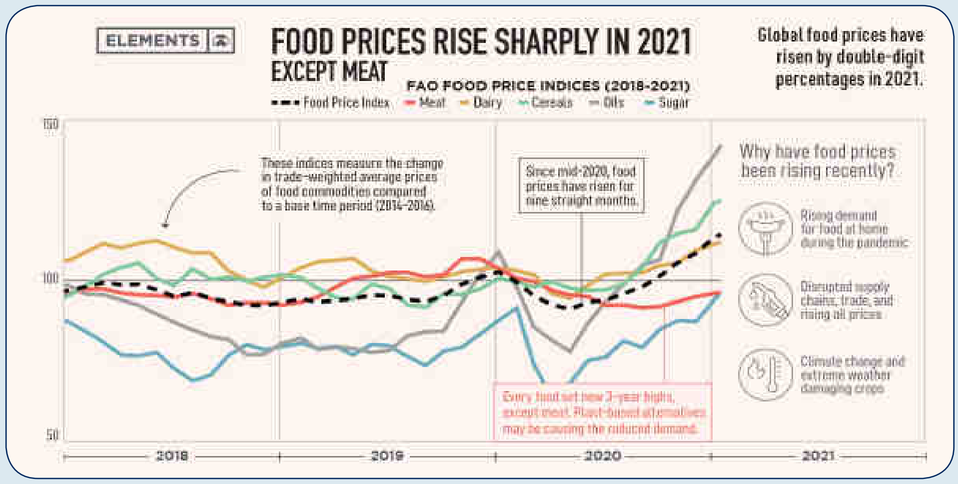

मांग मुख्य रूप से एशिया से थी। हालांकि मांस सूचकांक में 7% की वृद्धि हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में चीनी की कीमतों में 60% की वृद्धि हुई। यह मूल्य वृद्धि मुख्य रूप से ब्राजील में कम फसल के कारण और फ्रांस में फसल के नुकसान के कारण हुई।
- वनस्पति तेल की कीमतों में 8% की वृद्धि हुई। जबकि गेहूं के निर्यात की कीमतों में सबसे अधिक गिरावट आई है, जो महीने में 2.4% की गिरावट रही, यह अच्छी आपूर्ति और 2021 फसलों के लिए उत्पादन की संभावनाओं को प्रोत्साहित करती है।

खाद्य और कृषि संगठन का पूर्वानुमान

- 2021-22 में, खाद्य और कृषि संगठन ने भविष्यवाणी की है कि 2020-21 की तुलना में गेहूं के उत्पादन में 0.5% की वृद्धि होगी।
- पूर्वानुमान मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि चीन, ब्राजील, अमेरिका और यूक्रेन जैसे देशों ने अपने फसल क्षेत्रों में वृद्धि की है।

खाद्य मूल्य सूचकांक

- खाद्य मूल्य सूचकांक तिलहन, अनाज, डेयरी उत्पाद, चीनी और मांस जैसे खाद्यान्नों की एक टोकरी के मासिक परिवर्तनों को मापता है। अप्रैल 2021 में, खाद्य मूल्य सूचकांक 120.9 था ,जबकि मार्च 2021 में यह 118. 9 था।

8. वैश्विक मीथेन आकलन

चर्चा का कारण

- जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 'वैश्विक मीथेन आकलनः मीथेन उत्सर्जन कम करने के लाभ और लागत' (Global Methane Assessment% Benefits and Costs of Mitigating Methane Emission) नामक एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में मीथेन उत्सर्जन में अत्यधिक कटौती करने पर बल दिया गया है साथ ही मीथेन गैस में कमी करने के फायदे गिनाए गए हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु

- मानव गतिविधि द्वारा उत्पन्न मीथेन गैस का उत्सर्जन, इस दशक में 45 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है, जिससे पेरिस जलवायु समझौते की शर्तों के अनुरूप, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में मदद मिलेगी।
- मीथेन गैस उत्सर्जन में कमी करने से हर साल लगभग 2 लाख 60 हजार लोगों की मौतें रोकी जा सकती हैं और लगभग 7 लाख 75 हजार, अस्थमा मरीजों के अस्पताल इलाज से भी बचा जा सकता है। साथ ही, लगभग ढाई करोड़ टन फसलों के नुकसान को भी टाला जा सकता है।
- रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है कि 1980 के दौर में जब से रिकॉर्ड दर्ज करना शुरू किया गया, तब से देखा गया है कि मानव गतिविधियों के कारण, मीथेन गैस उत्सर्जन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिये अन्तरराष्ट्रीय कार्रवाई की तत्काल दरकार है।
- जब वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण वर्ष, 2020 में आर्थिक गतिविधियाँ धीमी हुई तो कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन का एक अन्य रिकॉर्ड वर्ष दर्ज करने से बचा जा सका, मगर अमेरिका की समुद्री

और वातावरणीय प्रशासन एजेंसी (NOAA) के आँकड़े दिखाते हैं कि वातावरण में पहुँचने वाली मीथेन गैस की मात्रा, वर्ष 2020 के दौरान रिकॉर्ड ऊँचाई के स्तर पर पहुँच गई।

समाधान

- आकलन रिपोर्ट में आसानी से हासिल किये जा सकने वाले ऐसे समाधानों की पहचान की गई है जिनके जरिये, वर्ष 2030 तक, मीथेन उत्सर्जन में 30 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में।
- इसका अधिकांश या लगभग 60 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने में बहुत कम लागत आएगी, और लगभग आधे लक्ष्य में कोई लागत ही नहीं है, इसका मतलब है कि कम्पनियों को समुचित कार्रवाई करने के बदले, लाभ होगा।
- रिपोर्ट के अनुसार, मीथेन गैस में कटौती करने की सम्भावनाएँ देशों और क्षेत्रों के अनुसार भिन्न हैं। मसलन, यूरोप और भारत में, अधिकाँश सम्भावना अपशिष्ट क्षेत्र से उत्पन्न होती है, तो चीन में ये कोयला उत्पादन और मवेशियों से उत्पन्न होती है, उधर अफ्रीका में, मीथेन गैस उत्सर्जन मवेशियों, तेल और गैस के कारण उत्पन्न होती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ रुख, आवासीय और व्यावसायिक उर्जा कुशलता, और भोजन बर्बादी व अपशिष्ट को रोकने जैसे अतिरिक्त उपायों के जरिये भी, मीथेन उत्सर्जन में वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 15 प्रतिशत तक की कटौती सम्भव है।

मीथेन गैस

- मीथेन, ग्रीनहाउस गैस समूह की एक शक्तिशाली गैस है, जोकि पूर्व-औद्योगिक काल से लेकर अब तक हुई तापमान वृद्धि में, 30 प्रतिशत हिस्से के लिये जिम्मेदार है।
- मीथेन उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा तीन प्रमुख क्षेत्रों जीवाश्म ईंधन: 35%, लैंडफिल और अपशिष्ट: 20% और कृषि: 40% से आता है।
- मानव गतिविधि द्वारा उत्पन्न मीथेन गैस का बड़ा हिस्सा इन प्रमुख तीन क्षेत्रों से आता है: तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से; विशाल कूड़ा घरों से जहाँ इनसानों द्वारा फेंका गया कूड़ा-कचरा इकट्ठा होता है; और खेतीबाड़ी से - मुख्य रूप से मवेशियों से सम्बन्धित।
- वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में, मीथेन का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत है।

9. स्पेसएक्स डॉग -1 मिशन टू द मून

चर्चा का कारण

- एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अगले साल यानी 2022 में 'DOGE -1 मिशन टू द मून' लॉन्च करेगी, जिसका भुगतान कनाडा की कंपनी जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन द्वारा क्रिप्टोकरेंसी डॉगकॉइन (dogecoin) के रूप में किया जाएगा।
- यह मिशन पृथ्वी की कक्षा से परे क्रिप्टोकरेंसी के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करेगा और इंटरप्लेनेटरी कॉमर्स के लिए नींव स्थापित करेगा।

क्रिप्टोकरेंसी डॉगकॉइन

- डॉगकॉइन एक क्रिप्टोकरेंसी है। इसकी शुरुआत साल 2013 में IBM के दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस (Billy Markus) और जैक्सन पामर (Jackson Palmer) के जरिए की गई थी।
- वहीं अब Dogecoin बिटकॉइन, इथीरियम और बाइनेंस कॉइन के बाद चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी बन गया है। डॉगकॉइन की तेजी में एलन मस्क का भी काफी साथ रहा है।
- इस डिजिटल करेंसी को एक वायरल डॉग मीम से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। करेंसी को कोई खास सफलता तो नहीं मिली लेकिन लंबे समय तक एक जोक की तरह इसका लेन-देन होता रहा।
- एलन मस्क ने डॉगकॉइन के समर्थन में कई ट्वीट किए, जिसकी मदद से इसमें तेजी देखने को मिली। इस साल फरवरी की शुरुआत में डॉगकॉइन की कीमत जहां 3.8 सेंट थी तो वहीं अब यह 3-4 महीनों में ही 73 सेंट तक का हाई बना लगा चुका है। डॉगकॉइन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है।

10. बेन्नू क्षुद्रग्रह (Bennu asteroid) और ओसीरिस-रेक्स अंतरिक्षयान (OSIRIS-REx Spacecraft)

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के ओसीरिस-रेक्स अंतरिक्षयान (OSIRIS-REx Spacecraft) ने बेन्नू क्षुद्रग्रह (Bennu asteroid) की सतह से वापस पृथ्वी की ओर उड़ान भरी है। ओसीरिस-रेक्स अंतरिक्षयान को पृथ्वी पर वापस पहुचने में लगभग दो वर्ष लगेंगे। नासा के ओसाइरस/ओसीरिस रेक्स अंतरिक्षयान (OSIRIS-REx Spacecraft) ने बेन्नू क्षुद्रग्रह की सतह से चट्टानों के नमूने एकत्र किए हैं। इससे सौर मंडल उत्पत्ति का पता लगाने में मदद मिल सकती है।

ओसीरिस-रेक्स अंतरिक्षयान (OSIRIS-REx Spacecraft) के बारे में

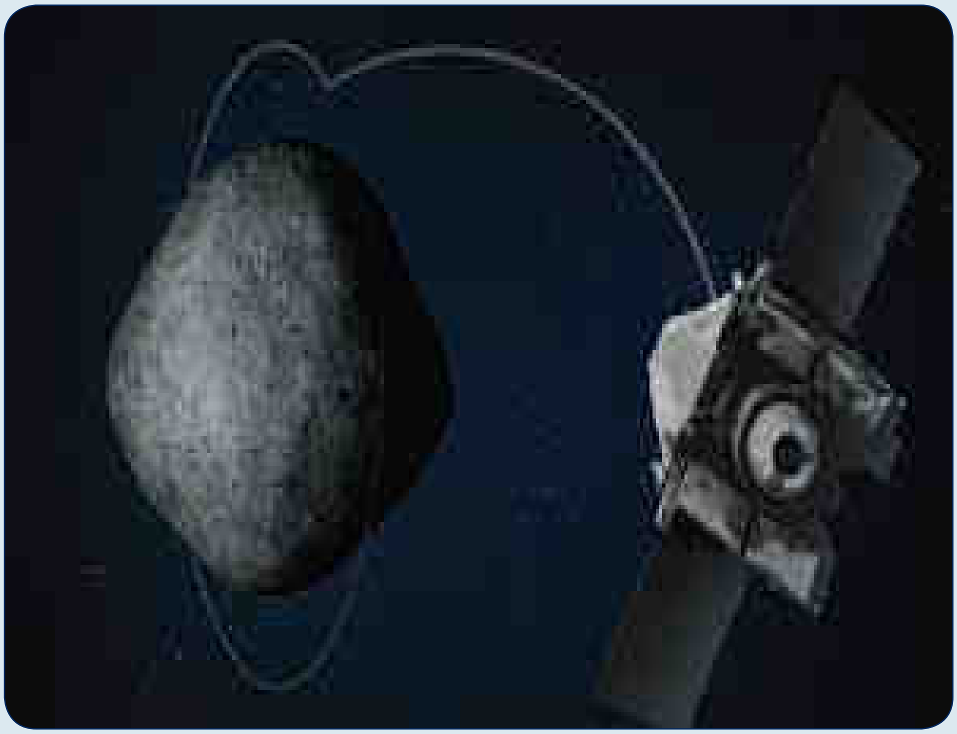

- नासा द्वारा फ्लोरिडा के केप केनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से 8 सितंबर, 2016 को अंतरिक्ष यान ओसीरिस-रेक्स (Osiris-REx) का प्रक्षेपण किया गया था।
- यह अंतरिक्ष यान लॉकहीड मार्टीन स्पेस सिस्टम्स द्वारा निर्मित किया गया है।
- ओसीरिस-रेक्स (Osiris-REx) का पूरा नाम-'Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer' है।
- यह एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है।
- नासा द्वारा यह अंतरिक्ष मिशन पृथ्वी के समीप के स्थित क्षुद्रग्रह बेन्नू से नमूने एकत्र करने और उनका अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया था।
- इस अन्तरिक्ष यान ने अपनी रोबोटिक भुजा की सहायता से क्षुद्र ग्रह की सतह से चट्टानों एवं खनिज तत्वों के नमूने एकत्र किए हैं।
- इस अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित पाँच उपकरण लगाए लगे हैं-
  - ओसीरिस-रेक्स लेजर अल्टीमीटर (OLA)
  - ओसीरिस-रेक्स थर्मल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर (OTES)
  - ओसीरिस-रेक्स विजिबल एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर (OVIRS)
  - ओसीरिस-रेक्स कैमरा सूट (OCAMS)
  - रेगोलिथ एक्स-रे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (REXIS)
  - किसी क्षुद्र ग्रह के नमूनों को एकत्रित कर पृथ्वी पर लौटने के लिये यह प्रथम अमेरिकी प्रयास है।

बेन्नू क्षुद्रग्रह के बारे में

- बेन्नू, एक क्षुद्रग्रह है जिसे '1999 RQ36' के नाम से भी जाना जाता है। इसे सबसे पहले 1999 में पृथ्वी के नजदीक से गुजरने के दौरान नासा की अन्तरिक्ष स्थित टेलीस्कोप से देखा गया था।

क्या होते हैं क्षुद्रग्रह (Asteroid)?

- क्षुद्रग्रह एक प्रकार के खगोलिय पिंड होते हैं जो ब्रह्माण्ड में गति करते रहते हैं। ये आपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडो से बड़े होते हैं। अधिकांश क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। ये सब भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित सेरेस (Ceres) क्षुद्रग्रह, सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका निर्माण सौरमंडल के निर्माण के साथ ही हुआ था एवं अतीत में इन क्षुद्रग्रहों के लम्बे काल तक पृथ्वी से टक्कर के चलते पृथ्वी के निर्माण में मदद मिली है।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित व्यक्ति

महाराणा प्रताप

गोपाल कृष्ण गोखले

रविंद्र नाथ टैगोर

एलन मस्क

हिमंत बिस्वा सरमा

पद्मकुमार एम. नायर

के.आर. गौरी अम्मा

महाराणा प्रताप

- हाल ही में मातृप्रेम, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक 'महाराणा प्रताप' की जयंती मनाई गई। उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप ने अपने अप्रतिम साहस, शौर्य और युद्ध कौशल से मां भारती को गौरवान्वित किया। मातृभूमि के लिये उनका त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा।

महाराणा प्रताप के बारे में

- महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता महाराजा उदयसिंह और माता राणी जीवत कंवर थीं। वह महान राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम 'कीका' था। बादशाह अकबर की साम्राज्यवादी नीति में मेवाड़ हमेशा एक सशक्त अवरोधक के रूप में प्रस्तुत हुआ। अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों से बचने के लिए उदयसिंह ने मेवाड़ को छोड़कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाई थी।

हल्दी घाटी का युद्ध

- हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून, 1576 को हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध मुगलों और राणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था । इसका नाम 'हल्दीघाटी' इसलिये पड़ा क्योंकि यहां की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी विशाल सेना को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ के लिए उतार दिया। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, महाराजा मानसिंह के साथ शाहजादा सलीम (जहांगीर) भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या 80 हजार से 1 लाख तक थी।
- इस विशाल मुगल सेना के सामने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया जिसमें कुल 20000 सैनिक शामिल थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना ने मुगल सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। जब परिस्थितियां विकट हुई और मुगल सेना हावी होने लगी, तब महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से

पीछे हट गए और गुरिल्ला पद्धति से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाए रखा। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगलों में भटकते हुए तृण-मूल व घास-पात की रोटियों में गुजर-बसर किया किंतु उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। बादशाह अकबर के 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद भी वह महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके। अंततोगत्वा युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। भारतीय इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा आज भी हमें मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वाभिमान और शौर्य के लिए प्रेरित करती है।

रविंद्र नाथ टैगोर

- हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर की जयंती मनाई गई है।

जीवन परिचय

- रविंद्र नाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को वर्तमान कोलकाता के जोड़ासाँ के ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के अग्रणी नेता थे। टैगोर परिवार का 'बंगाली पुनर्जागरण में' महत्वपूर्ण योगदान रहा। रविंद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई द्विजेन्द्रनाथ दार्शनिक और कवि थे वही उनके दूसरे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। 1883 में रविंद्र नाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। सन् 1901 में रविंद्र नाथ टैगोर शांतिनिकेतन गए और यहां पर एक आश्रम की स्थापना की। इस महान आत्मा ने सदा के लिए 7 अगस्त 1941 इस धरती को अलविदा कह दिया।

गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर का योगदान

- गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर विख्यात बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। रविंद्र नाथ टैगोर ने न केवल भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय कराया बल्कि पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में महती भूमिका निभाई। गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। वह दुनिया के एकमात्र अकेले

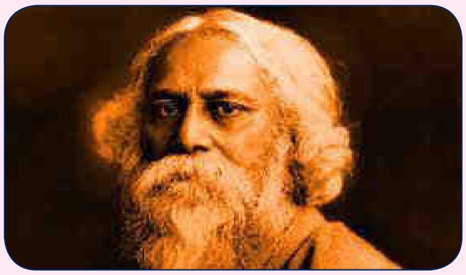

ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी-भारत का राष्ट्र-गान 'जन गण मन' और बाँग्लादेश का राष्ट्रीय गान 'आमार सोनार बाँग्ला'।

एक कला प्रेमी के रूप में रविंद्र नाथ टैगोर

- रविंद्र नाथ टैगोर को शुरुआती उम्र में ही कविता लिखने की रुचि विकसित हो गयी

थी। 1890 के दशक मे इनके कई सारी कविताएं, कहानियां और उपन्यास प्रकाशित हुए और वे बंगाल में प्रसिद्ध हो गए। 1913 में रविंद्र नाथ टैगोर को गीतांजलि की रचना की उनके इस कृति के आधार पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें 1915 में नाइटहुड उपाधि प्रदान की गई जिसे रविंद्र नाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया। रविंद्र नाथ टैगोर ने कविताओं के साथ साथ उपन्यास, लेख, लघु कहानियां, यात्रा-वृत्तांत, ड्रामा और हजारों गीत भी लिखे।

- रवीन्द्रनाथ के कुछ प्रमुख कृतियों में काबुलिवाला, नौकादुबी, गोरा, चतुरंगा, घारे बायर,जोगजोग, गीतांजली, गीताली, गीतिमाल्य, कथा ओ कहानी, शिशु, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेया आदि प्रमुख हैं। उनके द्वारा लिखे गए तकरीबन 2220 को रविंद्र गीत कहा जाता है जो बंगाली संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इनके कुछ महत्वपूर्ण गीतों में भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगीत शामिल है। इसके अलावा रविंद्र नाथ टैगोर एक कुशल चित्रकार भी थे। इस तरह हम देखे तो रविंद्र नाथ टैगोर ने एक उत्कृष्ट कलाकार की भांति कला से जुड़े हर एक विधाओं से भारतीय संस्कृति को वैविध्य बनाया।

गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध कथन

- गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर ने कहा था कि "राष्ट्रभक्ति (देशभक्ति) हमारी आध्यात्मिक शरणस्थली नहीं हो सकती। मेरी शरणस्थली मानवता है। मैं हीरे के बदले में कांच नहीं खरीदूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं मानवता के ऊपर राष्ट्रभक्ति (देशभक्ति) को हावी नहीं होने दूंगा।"

गोपाल कृष्ण गोखले

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले (Gopal Krishna Gokhale) को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित उनका जीवन देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।

गोपाल कृष्ण गोखले

- गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में शुमार हैं। इनको महात्मा गांधीजी जैसे व्यक्तित्व भी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। एक कुशल राजनीति के अलावा यह एक महान समाज सुधारक थे।
- गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण राव और उनकी माता का नाम वालूबाई था। अपनी हाईस्कूल की शिक्षा के उपरांत उन्होंने मुंबई के एलफिंस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होते हुए बाल गंगाधर तिलक व प्रोफेसर गोपाल गणेश आगरकर ने उन्हें मुंबई स्थित 'डेकन एजुकेशन सोसाइटी' से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस संस्थान में 20 वर्ष तक शिक्षक के रूप में कार्य किया। कृष्ण गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा का त्याग करते हुए एम.जी. रानाडे के निर्देशन में दक्कन सभा की स्थापना की। विदित है कि गोपाल कृष्ण गोखले दक्कन सभा की ओर से हुए इंग्लैंड में बेलबी आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए थे।
- बंगाल विभाजन के उपरांत जहां बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल और अरविन्द घोष जैसे गरम दल के नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया वहीं नरम दल की तरफ से गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अगुवाई की। ब्रिटिश सरकार गोपाल कृष्ण गोखले के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें लार्ड इजलिंगटन की अध्यक्षता में गठित पब्लिक सर्विसेज कमीशन के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का भी दौरा किया एवं वहां पर गांधीजी जी के भारतीयों के परिस्थितियों में सुधार हेतु किए जा रहे आंदोलन का भी समर्थन किया। लगातार खराब स्वास्थ्य रहने के कारण उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय पूना में व्यक्त किया। यहीं पर उन्होंने अपना आखरी राजनीतिक वक्तव्य दिया जिसे गोखले का 'राजनीतिक वसीयतनामा' कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह

'मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार योजना' का आधार बना। 19 फरवरी 1915 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।

सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

- सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा इसी वर्ष उन्होंने 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' का उद्देश्य था भारतीय लोगों को शिक्षित करना था। इसके अलावा, यह संस्था लोगों की सेवा के प्रति भी समर्पित थी।

एलन मस्क

- SpaceX के संस्थापक एलोन मस्क ने हाल ही में घोषणा की कि वे एस्परजर्स सिंड्रोम से प्रभावित हैं।

एलन मस्क

- एलन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 में उनका जन्म दक्षिण अफरीका में हुआ था. उनकी माँ मूल रूप से कनाडा की हैं और पिता दक्षिण अफ्रीका से हैं एलन मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी-कनाडाई-अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक और इंजीनियर हैं। एलन स्पेसएक्स के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर; टेस्ला कंपनी के सह-संस्थापक, सीईओ और उत्पाद के वास्तुकार; ओपनएआई के सह-अध्यक्ष; न्यूरालिंक के संस्थापक और सीईओ और द बोरिंग कंपनी के संस्थापक हैं।
- दिसंबर 2016 में, एलन को फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वाँ स्थान प्राप्त हुआ। 08 जनवरी 2021 तक, एलन की कुल संपत्ति 184 अरब अमेरिकी डॉलर है, और फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

एस्परजर्स सिंड्रोम क्या है?

- यह एक ऐसा विकार है जिसमे लोगों को सामाजिक रिश्तों में परेशानी होती है। एस्परजर्स सिंड्रोम का नाम जर्मन डॉक्टर हंस एस्परजर (Hans Asperger) के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 1944 में पहली बार विकार के बारे में बताया था। यह एक तरह का ऑटिज्म विकार है। यह किसी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से बाधित करता है।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर (Autism Spectrum Disorder)

- एस्परजर्स सिंड्रोम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। हालांकि, एस्परजर्स सिंड्रोम अन्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों से अलग है। ये व्यक्ति केवल सामाजिक संपर्क में कठिनाइयों का सामना करते हैं। एस्परजर्स सिंड्रोम के कारण अज्ञात हैं। यह माता-पिता से विरासत में मिलता है। 2019 तक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज (International Classification of Diseases) में एस्परजर्स सिंड्रोम बना हुआ है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज (ICD) को मेन्टेन किया जाता है। यह व्यापक रूप से रुग्णता और मृत्यु दर के आंकड़ों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। ICD का 11वां संस्करण 2019 में किया गया था और यह जनवरी 2022 में लागू होगा। मूल रूप से, यह स्वास्थ्य जानकारी और मृत्यु के कारणों के लिए एक वैश्विक मानक है। इसमें हजारों इकाइयां शामिल हैं।

के.आर. गौरी अम्मा

- दक्षिण भारत खास तौर पर केरल की राजनीति में आयरन लेडी के नाम से पहचानी जाने वाली कम्युनिस्ट नेता के आर गौरी अम्मा (K R Gauri Amma) का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया।

गौरी अम्मा

- अरुमुरी परम्बिल पार्वती अम्मा और कलाथिलपरम्बिल रमन की बेटी का जन्म 14 जुलाई, 1919 को अलाप्पुझा जिले में हुआ था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की। बाद में वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बन गई। उन्होंने अनपढ़ वर्गों और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई। केआर गौरी अम्मा 1957 में ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली पहली कम्युनिस्ट सरकार में राजस्व मंत्री रही। के आर गौरी अम्मा ने गरीबों को लेकर कई काम किए। इनमें सबसे बड़ा काम भूमि सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार विधेयक की शुरुआत करना रहा।

चुनाव

- 1948 में, उन्होंने थुरवुर निर्वाचन क्षेत्र से थिरु-कोची के खिलाफ चुनाव लड़ा। वह इस चुनाव में हार गई। हालाँकि, वह 1952 और 1954 में हुए चुनावों में जीतीं।
- 1957 में, जब केरल विधानसभा का पहला चुनाव हुआ, तो गौरी अम्मा सफलतापूर्वक चुनाव लड़ीं और राज्य की पहली राजस्व मंत्री बनीं। उन्होंने अपने जीवन में 17 चुनाव लड़े थे। और उनमें से 13 जीते थे। वह छह सरकारों में मंत्री पद पर रहीं।

जनतिपथ्य संरक्षण समिति

- 1994 में, गौरी अम्मा को नेतृत्व के साथ

विचार में मतभेद के अंतर के कारण सीपीएम से बाहर कर दिया गया था। इस प्रकार उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसे जनतिपथ्य संरक्षण समिति कहा जाता है।

हिमंत बिस्वा सरमा

- हाल ही में हिमंत बिस्वा सरमा ने 10 मई 2021 को असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल की जगह ली है।

जीवन परिचय

- हेमंत बिस्वा सरमा का जन्म 1 फरवरी 1969 को उलूबारी में हुआ था। साल 1990 में ग्रैजुएशन, 1992 में पोस्ट ग्रैजुएशन की पढ़ाई उन्होंने गुवाहाटी से ही की। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की जिसके बाद उन्होंने 1996-2001 तक गुवाहाटी की हाईकोर्ट में बतौर वकील काम किया.

राजनीतिक करियर की शुरुआत

- हेमंत बिस्वा सरमा ने साल 2001 में अपने राजनीतिक करियर की पहली बार शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। साल 2001 में पहली बार वे जालुकबरी से कांग्रेस के टिकट पर चनाव लड़े और जीत भी दर्ज की, इसके बाद इसी वे कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से लागातर तीन बार विधायक बनें। इसके

बाद गोगोई सरकार में उन्होंने वित्त, कृषि, प्लानिंग एव डेवलपमेंट, हेल्थ व परिवार कल्याण मंत्रालय का पद संभाल चुके हैं।

पद्मकुमार एम. नायर

- हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के पद्मकुमार माधवन नायर को बैड बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। दरअसल, बैड बैंक National Asset Reconstruction Company (NARC) की एक प्रस्तावित इकाई है।

पद्मकुमार नायर के बारे में

- वर्तमान श्री नायर एसबीआई के स्ट्रेस्ड एसेट्स (Stressed Assets) के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं। वह अप्रैल, 2020 से इस पद को संभाल रहे हैं। इससे पहले, उन्होंने SARG में महाप्रबंधक के रूप में काम किया था।

बैड बैंक (Bad Bank) क्या है?

- यह एक वित्तीय संगठन है जो उधारदाताओं की खराब संपत्ति (bad assets) को लेता है और उनका हल करता है। यह संस्थाएं अपनी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को बाजार मूल्य पर बैड बैंकों को बेच देंगी।
- इसका सुझाव इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने दिया था।
- भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry) ने वित्त मंत्रालय को "Multiple Bad Banks" स्थापित करने के लिए कहा था।
- बैड बैंक वित्तीय संगठनों को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स के बोझ से मुक्त करते हैं।इससे उन्हें

नए ऋणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

- फरवरी 2021 में, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने उन खराब ऋणों की पहचान की थी जिन्हें केंद्र सरकार के प्रस्तावित बैड बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित स्थान

दहला बांध

लितानी नदी

मियां का बाड़ा

माउंट सिनाबंग

बद्रीनाथ धाम

यरूशलेम

कैस्पियन सागर

कैस्पियन सागर

- हाल ही में मॉस्को मरीन मैमल्स रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं ने यह जानकारी दी है कि, रूस के डैगस्टान गणराज्य में कैस्पियन सागर के तट पर पिछले कई दिनों के दौरान कम से कम 170 लुप्तप्राय सील्स मृत पाई गई है। शोधकर्ताओं के अनुसार, दागास्तान की राजधानी माखचक्ला से लगभग 100 किमी दक्षिण में ये मृत सील पाए गए. जबकि कुछ अन्य मृत सील्स शहर के उत्तर में 50 किमी की दूरी पर मिले हैं।

कैस्पियन सागर

- दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल, कैस्पियन सागर, 5 देशों से घिरा है: कजाकिस्तान, ईरान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। विभिन्न जानकारों के मुताबिक, अब लगभग 70,000 कैस्पियन सील्स हैं जो 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में एक मिलियन से अधिक थे। दिसंबर, 2020 में अधिकारियों ने दागिस्तान के कैस्पियन तट पर लगभग 300 लुप्तप्राय सील्स की मौत की सूचना दी थी।

कैस्पियन सागर में प्रदूषण

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कहना है कि कैस्पियन सागर भारी प्रदूषण से पीड़ित है।
- इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - अपतटीय तेल क्षेत्र
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रेडियोधर्मी अपशिष्ट
  - वोल्गा रोवर द्वारा पेश औद्योगिक अपशिष्ट

प्रभाव

- कैस्पियन सागर सेंटीमीटर की दर से सिकुड़ रहा है। इसका मुख्य कारण समुद्र का बढ़ता वाष्पीकरण और सर्दियों में बर्फ का तेजी से पिघलना आदि है। इसके अलावा मृत जोन समुद्र के गहरे भागों में उभर रहे हैं। कैस्पियन सागर के सिकुड़ने से क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होंगे। शिपिंग मार्ग बहुत प्रभावित होंगे। प्रसिद्ध आर्द्रभूमि गायब हो जाएगी, मछली पकड़ने के श्रोत समाप्त हो जाएंगे, मछली पकड़ने के लिए पानी साझा करने में अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ सकता है, सर्दियों की बर्फ पूरी तरह से गायब हो सकती है।

माउंट सिनाबुंग

- इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी फिर से भड़क हो उठा है। माउंट सिनाबंग में 6 मई को विस्फोट शुरू हुआ है।

माउंट सिनाबुंग

- माउंट सिनाबुंग में 2010 में 400 वर्ष बाद विस्फोट हुआ था, उसके बाद 2013 में इसमें पुन: विस्फोट हुआ। उसके बाद से यह ज्वालामुखी काफी सक्रिय रहा। 2016 में इस ज्वालामुखी में एक भयानक विस्फोट हुआ था जिसमे सात लोगों की मृत्यु हो गयी थी। यह ज्वालामुखी 2,475 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में कारो जिले में स्थित है। यह लेक तोबा सुपरवोल्केनो से 40 किलोमीटर दूर है।

परिप्रशांत महासागरीय मेखला (Circum & Pacific Belt)

- इंडोनेशिया में, 'रिंग ऑफ फायर' अथवा परिप्रशांत महासागरीय मेखला (Circum & Pacific Belt) में अवस्थिति होने के कारण, कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, प्रशांत महासागर के चारो ओर विस्तृत क्षेत्र है तथा निरंतर होने वाली भूकंपीय घटनाओं तथा ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। 'रिंग ऑफ फायर' में विश्व के लगभग 75 प्रतिशत ज्वालामुखी पाए जाते है तथा कुल भूकंपीय घटनाओं में से 90 प्रतिशत भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं।

ज्वालामुखी विस्फोट का कारण

- ज्वालामुखी का उद्गार, भूगार्भिक क्रियाओं के कारण पृथ्वी की मेंटल परत के पिघलने से निर्मित मैग्मा के सतह तक ऊपर उठने पर होता है। चूंकि, मैग्मा, ठोस शिलाओं की तुलना में हल्का होता है, जिस कारण यह छिद्रों तथा दरारों से होकर पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाता है। सतह पर स्फुटित होने के पश्चात इसे लावा कहा जाता है।
- कोई ज्वालामुखी सक्रिय, सुप्त अथवा या मृत अवस्था में हो सकता है। सभी ज्वालामुखी उद्गार विस्फोटक नहीं होते हैं। ज्वालामुखी में विस्फोट की तीव्रता मैग्मा की संरचना पर निर्भर करती है। जब मैग्मा पतला तथा तरल अवस्था में होता है, इसके साथ उपस्थित गैसें आसानी से निकल जाती है, तथा लावा सतह पर प्रवाहित हो जाता है। दूसरी ओर, मैग्मा के गाढ़ा तथा सघन होने पर, इसके साथ उपस्थित गैसें बच कर नहीं निकल पाती हैं, जिससे पृथ्वी की आंतरिक सतह में दबाव निर्मित हो जाता है। भूगार्भिक हलचलों के कारण जिस स्थान पर भूपर्पटी कमजोर हो जाती है, वहां, आंतरिक भाग में उपस्थिति मैग्मा तथा गैसों के दबाव के कारण तेजी से ज्वालामुखी विस्फोट होता है।

दहला बांध

- हाल ही में, तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध – दहला बांध पर कब्जा कर लिया है। इस बांध का निर्माण करीब 70 साल पहले अमेरिका ने किया था। कांधार के सात जिलों में इससे सिंचाई की जाती है। 2019 में एशियन डिवेलपमेंट बैंक ने इसके लिए 350 मिलियन डॉलर का फंड भी मंजूर किया था। उल्लेखनीय है कि दाहला बांध कई नहरों के जरिए सिंचाई और प्रांतीय राजधानी को पीने का पानी उपलब्ध करता है

दहला बांध

- दहला बांध को अरगंडाब बांध के नाम से भी जाना जाता है।
- यह कंधार प्रांत, अफगानिस्तान के शाह वली कोट जिले में स्थित है।
- इसका निर्माण 1952 में USA द्वारा किया गया था।
- यह अरगंडाब नदी पर बना है।

अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित बांध

- काबुल नदी पर शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता।
- अफगानिस्तान-भारत मैत्री बांध (सलमा बांध)।

बद्रीनाथ धाम

- हाल ही में तेल क्षेत्र के पांच सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट आध्यात्मिक शहर (spiritual smart city) के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का समझौता किया है। विकास गतिविधियों में, नदी के तटबंधों पर किया जाना वाला कार्य, सभी इलाकों में वाहन मार्गों का निर्माण, पुल निर्माण, मौजूदा पुलों का सौंदर्यीकरण, आवास-सहित गुरुकुल सुविधाओं की स्थापना करना आदि शामिल होंगे। इन कार्यों पर होने वाले व्यय का वहन कंपनियों द्वारा अपने CSR फंड से किया जाएगा।
- केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार इस कदम से 'राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी' साथ ही तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम केदारनाथ, उत्तरकाशी, यमुनोत्री और गंगोत्री के विकास में भी योगदान देंगे।

बद्रीनाथ धाम

- बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी के तट पर गढ़वाल हिमालय में अवस्थित है। यह शहर, नीलकंठ चोटी (6,596 मी) से 9 किमी पूर्व, नर और नारायण पर्वत के मध्य स्थित है। बद्रीनाथ, नंदा

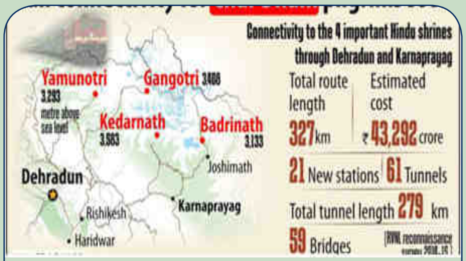

देवी चोटी के उत्तर पश्चिम में 62 किमी दूर और ऋषिकेश से 301 किमी उत्तर में स्थित है।

यरूशलेम

- हाल ही में, इजरायली सशस्त्र बलों ने यरूशलेम के हरम अश-शरीफ में स्थित अल-अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया जिसकी जवाबी कार्रवाई में, इस्लामिक आतंकवादी समूह 'हमास' (Hamas) द्वारा दर्जनों रॉकेट दागे गए। ज्ञातव्य है, कि गाजा पट्टी पर 'हमास' का नियंत्रण है।

यरूशलेम

- यरूशलम, शुरू से ही इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के केंद्र में रहा है। 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के मूल दस्त्वेजों के अनुसार, यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाना प्रस्तावित था। लेकिन वर्ष 1948 में हुए पहले अरब-इजरायल युद्ध में, इजरायलियों ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया, और जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। शहर के पूर्वी भाग में 'ओल्ड सिटी' भी शामिल है जिसमे 'हरम अश-शरीफ' स्थित है। उल्लेखनीय है कि अल-अक्सा मस्जिद (Al-Aqsa Mosque), इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और 'हरम अश-शरीफ' के भीतर 'चट्टानी गुंबद' (Dome of the Rock) स्थित है। इजराइल ने वर्ष 1967 हुए छह-दिवसीय युद्ध में, जॉर्डन के अधिकार में आने वाले पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और बाद में इसे अपने राज्य में शामिल कर लिया।
- यरुशलम इज्रायल और फिलिस्तीन देश की राजधानी है, जो कुछ देशों द्वारा विवादित है। ये यहूदी.पन्थ, ईसाई पन्थ और इस्लाम पन्थ, तीनों की पवित्र नगरी है।
- इतिहास गवाह है कि येरुशलम प्राचीन यहूदी राज्य का केन्द्र और राजधानी रहा है।
- यहीं यहूदियों का परमपवित्र सोलोमन मन्दिर हुआ करता था, जिसे रोमनों ने नष्ट कर दिया था।
- ये शहर ईसा मसीह की कर्मभूमि रहा है। यहीं से हजरत मुहम्मद जन्नत गए थे।
- राजधानी होने के अलावा यह एक महत्वपूर्ण

पर्यटन स्थल भी है।
- इस शहर में 158 गिरिजाघर तथा 73 मस्जिदें स्थित हैं।
- इन गिरिजाघरों और मस्जिदों के अलावा भी यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है।
- द इजरायल म्यूजियम, याद भसीम, नोबेल अभ्यारण, अल अक्सा मस्जिद, कुव्वत अल सकारा, मुसाला मरवान, सोलोमन टेम्पल, वेस्टर्न वॉल, डेबिडस गुम्बद आदि। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

लितानी नदी

- हाल ही में लेबनान की लितानी नदी पर में कारउन झील के तट पर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां बहकर आ गई। अत्यधिक प्रदूषण के कारण झील के किनारे लगभग 40 टन मछली मृत पायी गयी। स्थानीय ऐक्टिविस्ट अहमद आस्कर के अनुसार यह आपदा प्रदूषित पानी की वजह से आई लगती है, स्थानीय नदी प्रशासन ने कहा है कि मछलियां जहरीली थीं और उनमें कोई वायरस भी था। लोगों से यहां मछली न पकड़ने के लिए कहा है। इसे आपदा करार दिया गया है और लोगों के स्वास्थ्य को खतरा बताया गया है।
- लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है। इसमें एक कृत्रिम झील है जिसे लितानी नदी बांध द्वारा बनाया गया है, इस झील का नाम कारून झील (Qaraoun lake) है।

लितानी नदी

- यह नदी लेबनान के दक्षिणी भाग के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है।
- लितानी बांध का निर्माण 1959 में सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए किया गया था।
- यह बेक्का घाटी (Beqaa valley) से निकलती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है।

- लेबनॉन, आधिकारिक रूप से लुबनॉन गणराज्य, पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इसराइल स्थित है।

मियां का बाड़ा

- हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है।
- इससे पहले, अगस्त 2018 में, जोधपुर के निवासियों के शिकायत के बाद गाँव का नाम आधिकारिक तौर पर मियां का बाड़ा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण यहाँ के निवासियों द्वारा अपने बच्चों का वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न करवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनका तर्क था कि यह मुसलमानों के लिए बसा हुआ गाँव प्रतीत होता है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाम बदलने की मंजूरी दी थी और 2018 में राजस्थान सरकार को निर्णय दिया। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए एक समान अभ्यास दोहराया गया था।
- उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में, गृह मंत्रालय ने संसद को सूचित किया था कि 1 जनवरी, 2017 से 28 फरवरी, 2020 तक, उसे शहर / शहर / गाँव के नाम में परिवर्तन के लिए 67 प्रस्ताव

प्राप्त हुए थे और 52 प्रस्तावों को NOC प्रदान किया गया था।

❖❖❖

सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस

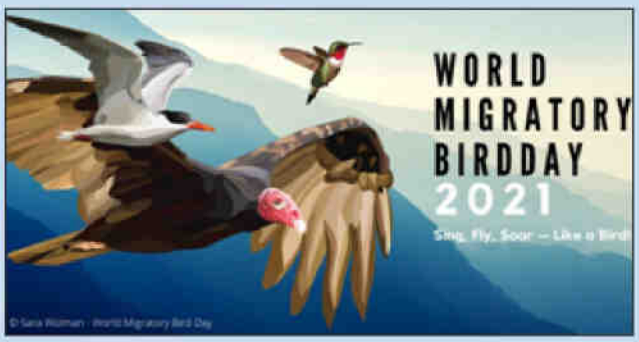

फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिवस

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस - 2021

रूसी विजय दिवस : 9 मई

फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिवस

- कोरोनावायरस महामारी के इस दौर में विश्व नर्स दिवस का महत्व काफी अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर्स के साथ-साथ नर्स अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल कर रही हैं। नर्सों को सम्मानित करने के लिए ही 'द लेडी विद द लैंप' के नाम से प्रसिद्ध फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के दिन यानि 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप मे मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि जनवरी 1974 में, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा की गई।

वर्ष 2021 नर्स डे की थीम

- प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के लिए एक विषय तय किया जाता है। इस वर्ष का विषय 'नेतृत्व के लिए एक आवाज: भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि' (नर्सेज-अ-वॉइस टू लीड- अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थकेयर) रखा गया है। इस विषय के आधार पर भविष्य में नर्सों के स्वास्थ्य सेवा में महत्व और नेतृत्व को लेकर काम किया जाएगा। स्वास्थ्य प्रणाली में डॉक्टर से अधिक नर्स का महत्त्व रहता है।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल

- 12 मई 1820 को विश्व की पहली और प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। वह एक ब्रिटिश नर्स, सांख्यिकीविद और समाज सुधारक थीं, जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थीं। क्रीमियन युद्ध के दौरान, उन्हें ब्रिटिश नर्सिंग और संबद्ध सैनिकों का प्रभार दिया गया था। वह वार्डों में कई घंटे बिताती थीं और पूरी रात वह मरीजों की देखभाल करती थीं, उनके पास जाती थीं, रात में हाथ में दीपक लेकर घूमती थीं और इसलिए उनकी छवि लेडी विद द लैंप के रूप में स्थापित की गई। नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक रूप देने के उनके प्रयासों के कारण, लंदन में सेंट थोमा अस्पताल में पहला वैज्ञानिक रूप से स्थित नर्सिंग स्कूल, नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग 1860 में खोला गया था। यह संस्थान वर्कहाउस इनफर्मियों में दाइयों और नर्सों के लिए प्रशिक्षण स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वह पहली महिला थीं जिन्हें 1907 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार

- नर्सिंग व्यवसाय को समाज में उचित सम्मान प्राप्त हो, इस वजह से हर साल 12 मई को देश में नर्सिंग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने की थी। अब तक कुल 250 के करीब नर्सों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया

गया है। इस पुरस्कार की अहमियत इसी बात से प्रकट होती है कि इसे देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में 50 हजार रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया जाता है।
- अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है-विश्व के विभिन्न देश इस दिन को विभिन्न तरीको से मनाते हैं। इस दिन को लंदन के वेस्टमिंस्टर ऐबी में एक कैंडल लैंप सेवा का आयोजन करके मनाया जाता है। इस आयोजन में कैंडल लैंप एक नर्स से दूसरे को सौंप दिया जाता है, जो कि एक नर्स से दूसरी नर्स के पास नॉलेज ट्रांसफर का प्रतीक है।
- अमेरिका और कनाडा में पूरे सप्ताह इसे नर्सिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी तमाम नर्सिंग समारोहों का आयोजन होता है।

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस

- हर साल 9 मई को दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (World Migratory Bird Day) मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के खतरों (पारिस्थितिक महत्त्व एवं संरक्षण) के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता से वैश्विक जागरूकता उत्पन्न करना है।

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय

- इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय "Sing, Fly, Soar – Like a Bird!" है, जबकि वर्ष 2020 का विषय 'पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं' (Birds Connect Our World) था।

पृष्ठभूमि

- ध्यातव्य है कि पहली बार 'विश्व प्रवासी पक्षी दिवस' को वर्ष 2006 में मनाया गया था। यह दिवस वर्ष में दो बार (मई एवं अक्तूबर महीने के दूसरे शनिवार को) मनाया जाता है।
- यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की दो संधियों ['वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन' (Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals-CMS)] एवं 'अफ्रीकन-यूरेशियन वॉटरबर्ड एग्रीमेंट' (AEWA) और एक गैर-लाभकारी

संगठन (एनवायरमेंट फॉर द अमेरिका-EFTA) के बीच एक सहयोगात्मक साझेदारी द्वारा मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस - 2021

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस-2021 (World Thalassemia Day-2021) मनाया गया है।
- वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस की थीम "एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी एक्रोस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी" है।

अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस

- 8 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस (World Thalassemia Day) मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य थैलेसीमिया के बारे में निर्णय और नीति निर्माणकर्ता, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले पेशेवरों, रोगियों और उनके परिवारों तथा समुदाय के मध्य जागरूकता बढाना है।

थैलेसीमिया रोग क्या है?

- थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार रोग है जो कि जीन के माध्यम से माता-पिता से बच्चों में संचारित होता है।
- इस रोग में हीमोग्लोबिन निर्माण के उत्तरदायी जींस या तो नष्ट हो जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं।
- उल्लेखनीय है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, जो कि शरीर के अंगों और ऊतकों में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है।
- हीमोग्लोबिन की क्षति या अपर्याप्तता के कारण; लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया उत्पन्न हो सकता है।
- थैलेसीमिया रोग में शरीर में लाल रक्त कण/रेड ब्लड सेल (आरबीसी) नहीं बन पाते हैं और जो थोड़े बन पाते हैं वह केवल थोड़े समय तक ही रहते हैं।
- थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को बार-बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा न करने पर बच्चा जीवित नहीं रह पाता है।

थैलेसीमिया के प्रकार

- **α-थैलेसीमिया (अल्फा थैलेसीमिया):** यह तब होता है जब 'α-हसवइपद प्रोटीन' से संबंधित जीन या जीन समूह अनुपस्थित या परिवर्तित (उत्परिवर्तित) हो जाते हैं।
- **β-थैलेसीमिया (या बीटा थैलेसीमिया):** यह तब होता है जब समान जीन दोष 'β-globin प्रोटीन' के उत्पादन को प्रभावित करते हैं।

थैलेसीमिया का इलाज

- थैलेसीमिया का पता रक्त परीक्षण से किया जाता है। यह उपचार योग्य रोग है।
- थैलेसीमिया मेजर के रोगियों के इलाज में क्रोनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, आयरन कीलेशन थेरेपी आदि शामिल हैं।
- इसमें कुछ ट्रांसफ्यूजन भी शामिल होते हैं, जो मरीज को स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की अस्थायी रूप से आपूर्ति करने के लिए आवश्यक होते हैं, ताकि उनमें हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो सके और रोगी के शरीर के लिए जरूरी ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम हो।
- कुछ बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट (अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण) से ठीक किया जा सकता है।

- इस प्रकार थैलेसेमिया अब घातक रोग नहीं है। प्रमाण दर्शाते हैं कि थैलेसेमिया से पीड़ित व्यक्ति उचित देखभाल और उपचार से लंबा और रचनात्मक जीवन जी सकता है तथा समाज में समाहित होकर अपना योगदान भी दे सकता है।

थैलेसेमिया से संबंधित राष्ट्रीय प्रयास

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), थैलेसेमिया सहित आनुवंशिक विकारों से पीड़ित बच्चों को प्रारंभिक जांच और उपचार प्रदान करता है।
- थैलेसेमिया से पीड़ित रोगी को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद द्वारा नि:शुल्क रक्त प्रदान किया जाता है।
- 'थैलेसेमिक्स इंडिया' जैसे कई गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भारत में थैलेसेमिया से मुकाबला करने में मदद करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

- भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (National Technology Day) मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम 'एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी' यानी (Science and Technology for a Sustainable Future) रखी गई है। जबकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2020 की थीम 'रीबूटिंग द इकोनॉमी विद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन' यानी (Rebooting the Economy through Science] Technology and Research Translations' titled 'RESTART') रखी गई थी।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का इतिहास

- 11 मई 1998 ही वो दिन था जब भारत ने 'ऑपरेशन शक्ति' के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद ही न्यूक्लियर हथियारों वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम शामिल हुआ था। इसके बाद 11 मई 1999 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को पहली बार मनाया गया और तब से यह दिन हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन का ऐलान तत्कालीन प्रधानमंत्री अलट बिहारी वाजपेयी ने किया था और इस दिन को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया था। इस दिन से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को तकनीकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित और प्रोत्साहित करता है।
- ध्यातव्य है कि 11 मई, 1998 को भारत के पहले स्वदेशी विमान, हंसा -1 ने उड़ान भरी।
- 11 मई, 1998 को ही रक्षा अनुसंधान एवं

विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सतह से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइल त्रिशूल मिसाइल का आखिरी टेस्ट-फायर को पूरा करके उसे भारतीय वायु सेना ने अपनी सेवा में शामिल किया।

रूसी विजय दिवस (Victory Day) : 9 मई

- कभी सोवियत संघ (USSR) का हिस्सा रहे रूस और दूसरे देशों में नाजी जर्मनी को हराने पर 9 मई का दिन श्टपबजवतल क्लश यानी विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अर्थात दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनों के आत्मसमर्पण को चिह्नित करने के लिए रूस में विजय दिवस मनाया जाता है।

मास्को विजय दिवस परेड के बारे में

- गत 9 मई, 2021 को, रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 76वीं वर्षगांठ मनाया है । मॉस्को के रेड स्क्वायर पर एक सैन्य परेड आयोजित की गई थी। यह परेड 1995 से हर साल 9 मई को आयोजित की जाती है। इस परेड को "मॉस्को विक्ट्री डे परेड" कहा जाता है।उल्लेखनीय है कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद ही विजय दिवस परेड एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया।इसी उपलक्ष्य में रेड स्क्वायर को 1990 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है।
- 1945 में, सोवियत सशस्त्र बलों ने नाजी सेना को हराने के बाद रेड स्क्वायर में एक सैन्य परेड आयोजित की। यह रेड स्क्वायर में आयोजित सबसे लंबी और सबसे बड़ी सैन्य परेड थी। इस परेड में 40,000 से अधिक सैनिकों और 1,850 सैन्य वाहनों ने भाग लिया था।यह परेड 24 जून, 1945 में आयोजित की गयी थी। जर्मन कमांडरों के आत्मसमर्पण के एक महीने बाद यह आयोजित की गयी थी। जर्मनों ने 9 मई, 1945 को आत्मसमर्पण किया था।

जर्मन आत्मसमर्पण दस्तावेज

- जर्मन आत्मसमर्पण दस्तावेज पर 7 मई, 1945 को जर्मन के चीफ ऑफ स्टाफ अल्फ्रेड जोडी ने हस्ताक्षर किये थे। 9 मई, 1945 को बर्लिन के बाहरी इलाके में एक अन्य आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये गये थे। आत्मसमर्पण के दोनों दस्तावेजों के अनुसार जर्मन सेना के सक्रिय संचालन पर रोक लगाई गयी थी।

❖❖❖

ब्रेन बूस्टर

01 राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैट्री भंडारण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 'राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैट्री भंडारण कार्यक्रम' (National Programme on Advanced Chemistry Cell Battery Storage) को मंजूरी दी है।

2. क्या है 'राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैट्री भंडारण कार्यक्रम'?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 'राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैट्री भंडारण कार्यक्रम' (National Programme on Advanced Chemistry Cell Battery Storage) को मंजूरी दे दी है।
- भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने इस योजना का प्रस्ताव रखा था।
- इसे नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज (National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage) द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इन दोनों को नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- इस योजना के तहत 50 गीगावॉट ऑवर्स (Giga Watt Hour-GWh) की एसीसी बैट्री की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- विदित हो कि गीगावॉट ऑवर्स का अर्थ एक घंटे में एक अरब वॉट ऊर्जा प्रति घंटा निर्माण करना है।
- इसके अतिरिक्त, इस योजना का लक्ष्य 5 गीगावॉट ऑवर्स की "उपयुक्त" (Niche) एसीसी बैट्री की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य भी है।
- इसकी लागत 18,100 करोड़ रुपये है।
- इसके अलावा 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैट्री भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी है। इससे 45,000 करोड़ रुपये का विदेशी और घरेलू निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

3. उन्नत रसायन सेल (Advanced Chemistry Cell-ACC)

- उन्नत रसायन सेल (Advanced Chemistry Cell-ACC) नई पीढ़ी की बैट्री है।
- एसीसी के तहत बिजली को इलेक्ट्रो-कैमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। जब जरूरत पड़े, तो इसे फिर से बिजली में बदला जा सकता है।
- आने वाले दिनों में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली से चलने वाले वाहन, उन्नत विद्युत ग्रिड, सौर ऊर्जा आदि में इस तरह की बैट्री की भारी मांग होगी।

4. 'राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैट्री भंडारण कार्यक्रम' से संभावित लाभ और परिणाम

- इस कार्यक्रम के तहत भारत में कुल 50 गीगावॉट ऑवर्स की एसीसी निर्माण सुविधा की स्थापना होगी।
- एसीसी बैट्री भंडारण निर्माण परियोजनाओं में लगभग 45,000 करोड़ रुपये का निवेश आयेगा।
- भारत में बैट्री निर्माण की मांग को पूरा किया जा सकेगा।
- मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
- इस योजना के तहत एसीसी बैट्री निर्माण से विद्युत चालित वाहन (ईवी) को प्रोत्साहन मिलेगा और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी। इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकेगा। साथ ही इससे 2 से 2.50 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
- एसीसी में उच्च विशिष्ट ऊर्जा सघनता को हासिल करने के लिये अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- नई और अनुकूल बैट्री प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार यह जलवायु परिवर्तन, हरित वृद्धि, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिये काफी फायदेमंद पहल है। यह विदेशी के साथ-साथ घरेलू निवेश लाएगा और रोजगार के अवसर सृजित करेगा।
- हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपये का आयात बचेगा।
- एसीसी में उच्च विशिष्ट एनर्जी सघनता को हासिल करने के लिये अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन।
- नई और अनुकूल बैट्री प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन।

02 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विकास परियोजना

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के लिये नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की मंजूरी दी गई है।

2. मुख्य बिन्दु

- हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की पर्यावरण मूल्यांकन समिति (Environment Appraisal Committee- EAC) ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के ग्रेट निकोबार द्वीप हेतु नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की मंजूरी दे दी है।
- हालांकि पूर्व में पर्यावरण मूल्यांकन समिति (EAC) ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। लेकिन समिति ने अब इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की मंजूरी दी है।

3. नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना

- नीति आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न द्वीपों व क्षेत्रों (यथा- ग्रेट निकोबार द्वीप, लिटिल अंडमान द्वीप आदि) के लिए विकासात्मक परियोजना का माडल बनाया है। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त, 2020 में घोषणा की थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 'मेरीटाइम एंड स्टार्टअप हब' के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके बाद से नीति आयोग ने इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए विकासात्मक परियोजना का माडल बनाया था। इसके लिए नीति आयोग ने विजन डॉक्यूमेंट भी पेश किया है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की जाएंगी, यथा-
  - अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र, टाउनशिप कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर, अस्पताल, विशेष वन रिसॉर्ट।
- गौरतलब है कि नीति आयोग ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में लिटिल अंडमान द्वीप के लिए एक मेगासिटी प्लान (megacity plan) का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। यह मेगासिटी लिटिल अंडमान द्वीप के 680 वर्ग किमी क्षेत्र में विकसित की जाएगी। इसके तहत एक नई ग्रीनफील्ड तटीय शहर (New Greenfield Coastal City) बनाकर तैयार की जाएगी, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Zone) के रूप में विकसित किया जाएगा। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। इसमें अंडरवाटर रिजॉर्ट्स, कसीनो, गोल्फ कोर्स, कन्वेंशन सेंटर,अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अस्पताल, विशेष वन रिसॉर्ट इत्यादि का भी विकास किया जाएगा।

4. नीति आयोग की विकासात्मक परियोजना से संबन्धित मुद्दे

- नीति आयोग की अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए इस विकासात्मक परियोजना की पर्यावरणविदों द्वारा आलोचना की जा रही है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न क्षेत्रों को काफी क्षति होगी और यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा। कुछ पर्यावरणविदों ने निम्नलिखित तीन आधारों पर इस विकासात्मक परियोजना के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं-
  - पारिस्थितिकी संवेदनशीलता (Ecological Fragility)
  - स्थानीय अधिकार (Indigenous Rights)
  - भूकंप और सुनामी के प्रति सुभेद्यता (Vulnerability to Earthquakes and Tsunamis)

5. नीति आयोग का तर्क

- नीति आयोग का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए विकासात्मक परियोजना से इस पूरे क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा।
- इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व में और इजाफा होगा।
- इस विकासात्मक परियोजना से स्थायी और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।

6. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बारे में

- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है, जिसमें छोटे-बड़े लगभग 576 द्वीप शामिल हैं।
- इन द्वीपों को दो प्रमुख द्वीपसमूहों में बाँटा गया है - उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह।
- अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 100 चैनल द्वारा एक-दूसरे से अलग होते हैं।
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पूर्व में स्थित अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार देशों से अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी 'बैरन द्वीप' यहीं स्थित है।
- अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पारिस्थितिकी तंत्र में कठोर या चट्टानी प्रवाल की 555 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो पर्यावरणीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं।
- इसके अतिरिक्त, लंबे समय तक मुख्य भूमि से अलगाव के कारण ये द्वीप कई प्रजातियों के उद्भव के लिए हॉटस्पॉट बने, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों स्थानिक प्रजातियाँ और उप प्रजातियाँ यहाँ विकसित हुई हैं।

03 इजराइल का आयरन डोम रॉकेट रक्षा प्रणाली

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष में दोनों पक्षों द्वारा हवाई हमले और रॉकेट हमले जारी हैं। फिलस्तीनी उग्रवादी गुट हमास ने अब तक इजरायल पर 1700 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इनमें से ज्यादातर रॉकेट को इजरायल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। हमास के इस रॉकेट की बारिश का इजरायल के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि इजरायल का लौह कवच कहे जाने वाले आयरन डोम सिस्टम ने हमास के 90 फीसदी रॉकेट को बीच रास्ते में ही मार गिराया।

2. आयरन डोम रॉकेट रक्षा प्रणाली के बारे में

- 'आयरन डोम' एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रॉकेट, तोपखाने और मोर्टारों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम दिन और रात दोनों ही समय काम करने में सक्षम है। इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया है।
- आयरन डोम' (Iron Dome), वर्ष 2011 में तैनात की गई एक कम दूरी की, सतह से हवाई सुरक्षा करने वाली 'वायु रक्षा प्रणाली' है।
- यह प्रणाली 'रडार' और 'तामिर (Tamir) इंटरसेप्टर मिसाइल' से लैस है, जो इजरायल पर हमला करने वाली मिसाइलों या रॉकेटो को ट्रैक करके बेअसर कर देती है।
- इसका उपयोग विमानों, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहनों के साथ-साथ रॉकेट, तोपों और मोर्टार का प्रतिरोध (Countering Rockets] Artillery & Mortars: C-RAM) करने के लिए किया जाता है।
- इसकी सफलता दर 90% से अधिक है।

3. आयरन डोम रॉकेट रक्षा प्रणाली कैसे काम करता है?

- आयरन डोम में तीन मुख्य प्रणालियाँ होती हैं, जो अपनी तैनाती-क्षेत्र को सुरक्षा-कवच प्रदान करने तथा विभिन्न खतरों को संभालने के लिए एक साथ कार्य करती हैं।
- इसमें, आने वाले किसी भी खतरे की सूचना देने और उसका पीछा करने के लिए एक 'रडार', एक युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली (battle management and weapon control system- BMC), तथा एक 'मिसाइल फायरिंग यूनिट' लगी होती है।
- 'आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम', दिन-रात और सभी मौसम में कार्य करने में सक्षम है।
- सबसे पहले यह रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्र की दिशा की जांच करता है और वॉर्निंग सायरन बजाता है।
- सायरन बजने के बाद स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय होता है।
- इसके बाद आयरन डोम अपने रेडॉर की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए 'आयरन डोम' ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है।
- आयरन डोम के प्रत्येक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इन मिसाइलों में रॉकेट और मिसाइलों को ट्रेस करने की बेजोड़ क्षमता होती है। यह 70 किमी की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद कर देता है।

4. भारत की रक्षा प्रणाली

- भारत के पास S-400 प्रणाली है, जो रॉकेट, मिसाइल और क्रूज मिसाइल के तीन खतरों से निपटने में सक्षम है। किंतु इनकी रेंज काफी अधिक होती है। S-400 प्रणाली, लगभग 300 से 400 किमी रेंज से दागी जाने वाली मिसाइलों, विमानों को मार गिराती है।
- फिलहाल इस समय, भारत के पास कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल, और एक रूसी प्रणाली 'पिकोरा' (Pechora) है।

04 क्वॉड के मुद्दे पर बांग्लादेश को चीन की धमकी

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने चेतावनी देते हुए बांग्लादेश को कहा था कि अगर बांग्लादेश चीन विरोधी गुट क्वॉड में शामिल होता है तो द्विपक्षीय संबंध रिश्ते बुरी तरह प्रभावित होंगे। हालांकि चीनी राजदूत की इस टिप्पणी पर बांग्लादेश ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बांग्लादेश की विदेश नीति गुट-निरपेक्ष और संतुलनवादी सिद्धांत पर आधारित है और वह उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगा।

2. प्रमुख बिन्दु

- क्वाड के सदस्य देश जरूरत के मुताबिक क्वाड के रणनीतिक विस्तार पर सहमत हैं। चीन की बांग्लादेश को धमकी को भी अमेरिका ने संज्ञान में लिया है। सदस्य देश हिंद-प्रशांत छेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाने और जरूरत के मुताबिक अन्य देशों से चर्चा करने को तैयार हैं।
- बांग्लादेश और मालदीव, दोनों देश सड़क, पुल, रेल नेटवर्क व अस्पतालों के निर्माण में जुटे हुए हैं। जापान इस इलाके में काफी निवेश को उत्सुक है और चीन इसे लेकर बौखलाहट में है।
- चीन का मानना है कि क्वाड उसे लक्ष्य करके बनाया गया है। सदस्य देश चीन के रणनीतिक हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हालांकि, भारत ने कई मौकों पर कहा है कि यह गठजोड़ किसी देश के खिलाफ नही है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता।

3. बांग्लादेश में चीन की मौजूदगी

- फाइनैंशियल टाइम्स के अनुसार चीन बांग्लादेश में 30 अरब डॉलर की परियोजना पर काम कर रहा है और गंगा नदी पर छह किलोमीटर लंबा यह पुल इसी परियोजना का हिस्सा है।
- बांग्लादेश में दक्षिणी और उत्तरी बांग्लादेश को जोड़ने वाला एक पुल बनकर तैयार हुआ है। छह किलोमीटर लंबा यह पुल दोनों इलाकों को सड़क और रेल के जरिए जोड़ता है। बांग्लादेश बनने के बाद से यह इंजीनियरिंग की सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजना थी जो बनकर तैयार हुई है।

4. क्वॉड समूह

- क्वॉड समूह में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। इसे अनौपचारिक रणनीतिक गठबंधन भी कहा जाता है। चीन और रूस इसे चीन विरोधी गुट कहते हैं।
- रूस ने इस समूह में भारत के शामिल होने पर भी आपत्ति जताई थी। रूसी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत पश्चिमी देशों की चीन विरोधी मुहिम का मोहरा बन रहा है। हालांकि भारत ने रूस की इस टिप्पणी को खारिज कर दिया था।
- क्वॉड को एशिया-पैसिफिक में चीन की बढ़ती ताकत से मुकाबला करने वाली अमेरिकी रणनीति के तौर पर भी देखा जाता है। अभी हाल ही में इस समूह की वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें चारों देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए थे।

05 COVID-19 का शहरी और ग्रामीण गरीबों पर प्रभाव

1. चर्चा में क्यों?

- हंगर वॉच (Hunger Watch) द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी ने भारत में शहरी गरीबों को ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक भुखमरी में धकेल दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो COVID-19 ने भारत के शहरी गरीबों को गांवों की तुलना में अधिक प्रभावित किया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- कोविड 19 संकट से उपजे हालात के बाद 11 राज्यों में 3,994 परिवारों के साथ साक्षात्कार के आधार पर डेटा अक्टूबर 2020 में एकत्र किया गया था और समान मापदंडों पर प्री-लॉकडाउन स्तरों के साथ उसकी तुलना की गई थी।
- हंगर वॉच के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के माध्यम से ग्रामीण निवासियों का एक बड़ा वर्ग महामारी से प्रेरित आर्थिक संकट को खत्म कर पाया, किन्तु शहरी गरीबों तक ऐसे राशन की पहुँच बहुत निम्न थी।
- शहरी गरीबों के आय में आधे या एक चौथाई की कमी आई जबकि ग्रामीण निवासियों के लिए यह एक तिहाई से थोड़ा अधिक था। शहरी गरीबों के लिए अनाज और दालों की खपत आवश्यकता से कम से कम 12 प्रतिशत कम थी। इसी प्रकार शहरी उत्तरदाताओं में पोषण गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट देखी गयी, क्योंकि आर्थिक बंदी के दौरान उनके पास पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं थे।
- लगभग 54 प्रतिशत शहरी उत्तरदाताओं ने भोजन के लिए पैसे उधार लिए जबकि 38 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने भोजन के लिए पैसे उधार लिए। कुछ 45 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं को अक्टूबर 2020 में भोजन छोड़ना पड़ा जबकि लगभग दो-तिहाई शहरी उत्तरदाताओं को एक ही महीने में ऐसा करना पड़ा।
- इसमें कहा गया है कि शहरी गरीबों द्वारा अनुभव किए गए बड़े झटके को देखते हुए, यह उम्मीद की गई थी कि केंद्रीय बजट में शहरी रोजगार कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ।

3. राशन कार्ड व सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से जुड़ी समस्याएँ

- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी ग्रामीण गरीबों के बीच अपेक्षाकृत बेहतर कवरेज था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस राशन की बेहतर पहुंच थी।इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों के एक बड़े हिस्से के पास राशन कार्ड नहीं है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी वाले भोजन और रोजगार गारंटी के प्रावधान की योजनाओं सहित सामाजिक सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

4. पोषण से जुड़ी चिंताएँ

- भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2018-19 (291.1 मिलियन टन) की तुलना में वर्ष 2019-20 (296.65 मिलियन टन) में 4% अधिक था, फिर भी भुखमरी की स्थिति पहले से व्यापक हो गई है और कुछ लोगों को तो पूरे दिन में आवश्यकता से कम भोजन मिल रहा है।
- इसके बावजूद, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ-साथ आत्मानिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किए गए गरीब और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रदान की गई अतिरिक्त सहायता अक्टूबर 2020 में समाप्त हो गई।

6. हंगर वॉच

- हंगर वॉच सामाजिक समूहों और आंदोलनों का एक संगठन है। यह मार्च 2020 में देशव्यापी तालाबंदी के मद्देनजर विभिन्न वंचित आबादी के बीच भूख, भोजन की पहुंच और आजीविका सुरक्षा की वास्तविक स्थिति के आवधिक अध्ययन के लिए कार्य कर रहा था।

5. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़े

- हंगर वॉच रिपोर्ट के आँकड़े और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों को साथ मिलाकर देखा जाये तो यह स्थिति बेहद चिंताजनक है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों ने कुपोषण के परिणामों में या तो बढ़ोत्तरी या ठहराव दर्शाया है, जैसे कि चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग (Wasting) का प्रचलन तथा महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया का उच्च स्तर।
- एनएफएचएस सर्वेक्षण 2019 में COVID-19 या लॉकडाउन की शुरुआत से पहले आयोजित किया गया था।

06 भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच बैठक

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-यूरोपीय संघ के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ शिखर बैठक की। यह प्रथम अवसर है जब यूरोपीय संघ ने भारत के साथ यूरोपीय संघ+27 प्रारूप में एक बैठक की मेजबानी की है।

2. प्रमुख बिन्दु

- भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के साथ साथ तीन प्रमुख विषयगत क्षेत्रों (i) विदेश नीति और सुरक्षा; (ii) कोविड-19, जलवायु और पर्यावरण तथा (iii) व्यापार, संपर्क और प्रौद्योगिकी पर विचार-विमर्श किया गया।
- सभी नेताओं ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला और आर्थिक सुधारों की दिशा में कार्य करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार लाने में निकट सहयोग करने पर भी विचार-विमर्श किया। भारत ने दूसरी कोविड लहर का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों द्वारा प्रदान की गई त्वरित सहायता की सराहना की।
- इस बैठक का एक प्रमुख परिणाम दोनों पक्षों को आर्थिक साझेदारी की पूर्ण क्षमता का अनुभव कराने में सक्षम बनाना है। भारत और यूरोपीय संघ ने डब्ल्यूटीओ मुद्दों, विनियामक सहयोग, बाजार पहुंच मुद्दों और आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन अपनाने पर समर्पित संवादों की घोषणा की, जो आर्थिक संबंधों को और मजबूत और भविष्य में और परिपुष्ट बनाने की इच्छा को प्रदर्शित करते हैं।
- भारत और यूरोपीय संघ ने डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक महत्वाकांक्षी और व्यापक संपर्क साझेदारी का भी शुभारंभ किया। यह साझेदारी सामाजिक, आर्थिक, राजकोषीय, जलवायु और पर्यावरणीय स्थिरता एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रतिबद्धताओं के सम्मान के साझा सिद्धांतों पर आधारित है। यह साझेदारी संपर्क परियोजनाओं के लिए निजी और सार्वजनिक वित्तपोषण को प्रोत्साहन देगी। यह भारत-प्रशांत सहित अन्य देशों में संपर्क पहल का समर्थन करने के लिए नए संबंधों को बढ़ावा देगी।

3. भारत और यूरोपीय संघ के बीच जलवायु मुद्दे को लेकर बातचीत

- भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन, अनुकूलन और लचीलेपन के संयुक्त प्रयासों को और दृढ़ बनाने के साथ-साथ सीओपी 26 के संदर्भ में वित्तपोषण सहित कार्यान्वयन के साधन प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।
- भारत ने सीडीआरआई में शामिल होने के यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया। भारत और यूरोपीय संघ ने डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे 5जी, एआई, क्वांटम और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भी सहमति व्यक्त की, जिसमें एआई और डिजिटल निवेश फोरम पर संयुक्त कार्यबल का प्रारंभिक परिचालन शामिल है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

4. क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत

- सभी नेताओं ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बढ़ती सामंजस्यता पर संतोष व्यक्त किया।
- वैश्विक नेताओं ने एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित भारत-प्रशांत के महत्व को स्वीकार किया और इस क्षेत्र में भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल और इंडो-पैसिफिक पर यूरोपीय संघ की नई रणनीति के संदर्भ में निकटता से जुड़ने पर भी सहमति जताई।

5. भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्व

- यूरोपीय संघ, भारत के लिये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समूह है और यह 2018 में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी रहा है।
- यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार वर्ष 2018-19 में 115.6 अरब डॉलर का था, जिसमें निर्यात 57.17 अरब डॉलर तथा आयात 58.42 अरब डॉलर का रहा।
- बैठक में भारत और यूरोपीय संघ ने संतुलित, महत्वाकांक्षी एवं समग्र कारोबार समझौते और 'स्टैंड-अलोन' निवेश संरक्षण समझौता पर बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई।

07 डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिये नीति आयोग की रिपोर्ट

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नीति आयोग और मास्टरकार्ड ने 'कनेक्टेड कॉमर्स' (connected commerce) शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन की राह में चुनौतियों की पहचान करती है। साथ ही 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवा की पहुंच करने की दिशा में जरूरी सिफारिशें देती है।

2. प्रमुख बिन्दु

- अक्टूबर और नवंबर 2020 में आयोजित पांच गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के आधार इस रिपोर्ट में प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कृषि, छोटे व्यवसाय (एमएसएमई), अरबन मोबिलिटी और साइबर सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण पर दी गई सिफारिशें शामिल हैं।
- भारत वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ा रहा है। इसके चलते उपभोक्ता नकदी की जगह कार्ड, वॉलेट, ऐप और यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। यह रिपोर्ट कुछ प्रमुख सेक्टर और क्षेत्रों पर नजर डालती है जिससे वित्तीय सेवाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल रुकावटों को खत्म करने की आवश्यकता है।
- विशेषज्ञों ने अक्टूबर और नवंबर के बीच डिजिटल वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए एमएसएमई को वैश्विक अवसरों का लाभ दिलाने में सक्षम बनाने, डिजिटल कॉमर्स को लेकर विश्वास और सुरक्षा बढ़ाने, भारत के कृषि उद्यमों को कनेक्टेड कॉमर्स के लिए तैयार करने और स्मार्ट सिटी के लिए मजबूत ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

3. रिपोर्ट में शामिल मुख्य सिफारिशें

- एनबीएफसी और बैंकों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना।
- एमएसएमई को अवसरों भुनाने में सक्षम करने के लिए पंजीयन और अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और क्रेडिट स्रोतों में विविधता लाना।
- 'फ्रॉड रिपॉजिटरी' सहित सूचना साझाकरण प्रणाली का निर्माण और यह सुनिश्चित करना कि ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम के प्रति सचेत करने के लिए चेतावनी भेजे।
- कृषि एनबीएफसी को कम लागत वाली पूंजी तक पहुंच बनाने के लिए सक्षम करना और बेहतर दीर्घकालिक डिजिटल परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक फिजिटल (भौतिक+डिजिटल) मॉडल को विस्तार करना। भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी इस क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देगा।
- न्यूनतम भीड़-भाड़ के साथ शहरों में ट्रांजिट को सुलभ बनाने के लिए मौजूदा स्मार्टफोन और कॉन्टेक्टलेस कार्ड का लाभ उठाते हुए, एक समावेशी, इंटरऑपरेबल, और पूरी तरह से खुले सिस्टम जैसे कि लंदन 'ट्यूब' बनाना।

4. निष्कर्ष

- कोविड-19 महामारी ने हम सभी को नकदी की समस्या और डिजिटल प्रौद्योगिकी के लचीलेपन के लिए सतर्क कर दिया है, जिसमें अन्य भुगतान भी शामिल हैं। प्रतिबंधों के साथ भी बुनियादी आजीविका की जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉमर्स को जारी रखने की जरूरत है और डिजिटल तकनीक ने इसे संभव बनाया है।
- अब पहले से कहीं अधिक छोटे कारोबारियों की पहुंच डिजिटल दुनिया में समानांतर होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल को अधिक सुलभ बनाने के लिए अपने परिचालन परिदृश्य में बड़ा बदलाव किया है। यह दुनिया में उन्नत डिजिटल भुगतान सेवाओं में से एक है।

स्वयं को जाँचें
(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

1. माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 'विभाजन रेखा'

प्र. माउंट एवरेस्ट शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है
2. दोनों देशों ने संयुक्त रूप से समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की 8,848.86 मीटर 'नई' ऊंचाई की घोषणा की थी
3. भारतीय सर्वेक्षण द्वारा 1954 के बाद से मान्यता प्राप्त माउंट एवरेस्ट ऊंचाई से 86 सेमी अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

2. तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

प्र. तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय' सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. आर्कटिक परिषद में सदस्य राज्य के रूप में आठ परिध्रुवीय देश हैं- कनाडा, डेन्मार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन तथा अमेरिका।
2. आर्कटिक परिषद की स्थापना वर्ष 1996 में 'ओटावा घोषणा' से हुई थी।
3. भारत को वर्ष 2013 से आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 1 और 2

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

3. मालदीव के निकट गिरा 'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई2' रॉकेट

प्र. 'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई2' (Long March-5B Y2) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई2' (Long March-5B Y2), एक चीनी रॉकेट है।
2. इस रॉकेट का उपयोग चीन, अन्तरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन के निर्माण हेतु कर रहा है।
3. 'लॉन्ग मार्च -5 बी वाई2' रॉकेट, हाल ही में चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण हेतु तीन प्रमुख घटकों में से प्रथम घटक 'तियान्हे मॉड्यूल' (Tianhe module) को लेकर गया था।

उपर्युक्त कथनों मे से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 3

(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

4. डबल्यूटीओ में पेटेंट संबंधी सुरक्षा से छूट को मंजूरी

प्र. डबल्यूटीओ में पेटेंट संबंधी सुरक्षा से छूट को मंजूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में एक प्रस्ताव दिया था कि कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट संबंधी सुरक्षा हटा ली जाए; ताकि विभिन्न फॉर्मा कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर कोरोना वैक्सीन का भारी मात्रा में उत्पादन कर सकें।
2. भारत और अन्य समान सोच वाले देशों द्वारा सक्रिय प्रयासों के परिणाम-स्वरूप इस प्रस्ताव को 120 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

5. 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज, आयुष-64 और काबासुरा कुडिनीर मेडिसिन

प्र. 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज, आयुष-64 और काबासुरा कुडिनीर मेडिसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज (आईएनएमएएस) द्वारा '2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी)' दवा का एक 'एंटी कोविड-19' चिकित्सकीय अनुप्रयोग विकसित किया गया है।
2. 'आयुष 64' दवा, सप्तपर्ण (Alstonia scholaris), कुटकी (Picrorhiza kurroa), चिरायता (Swertia chirata) एवं कुबेराक्ष (Caesalpinia crista) औषधियों से बनी है।
3. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय तथा सीएसआईआर (CSIR) के द्वारा तैयार 'आयुष 64' दवा हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए लाभकारी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (A)

6. सोशल स्टॉक एक्सचेंज

प्र. सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) स्टॉक एक्सचेंजों पर गैर-लाभकारी या गैर-सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है।
2. इसके तहत उन्हें एक वैकल्पिक फंड जुटाने वाली संरचना प्रदान करता है।
3. इसे बीएसई (BSE) या एनएसई (NSE) पर सूचीबद्ध किया जा सकता है।
4. यूके, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों में सोशल स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 2 और 4
(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

7. मराठा आरक्षण असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय

प्र. मराठा आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. महाराष्ट्र एसईबीसी अधिनियम, 2018 नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता था।
2. 2018 में इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दे दिया।
3. जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

8. स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021: वन ईयर ऑफ कोविड-19' रिपोर्ट

प्र. स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021: वन ईयर ऑफ कोविड-19' रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. रिपोर्ट के मुताबिक कोविड का सबसे ज्यादा असर युवा कामगारों पर पड़ा है।
2. 15-24 वर्ष के आयु वर्ग में 33 फीसदी लोगों को दिसंबर 2020 तक रोजगार नहीं मिला जबकि 25 से 44 साल के बीच 6 फीसदी लोग रोजगार गंवा चुके थे।
3. कोरोना संकट की सबसे बड़ी मार अमीरों पर पड़ी पड़ी है।
4. रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी इलाकों में गरीबी 40 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में 25 फीसदी तक बढ़ गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही नहीं हैं?

(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1 और 2
(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (C)

9. ब्लैक फंगस

प्र. ब्लैक फंगस के संदर्भ मे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 'म्यूकोर माइकोसिस' नामक इस फंगल संक्रमण को सामान्य बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है।
2. भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, म्यूकर माइकोसिस एक तरह का दुर्लभ फंगल इंफेक्शन है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलता है।
3. यह संक्रमण मस्तिष्क, फेफड़े और त्वचा पर भी असर कर रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

10. भारत में 5G इंटरनेट तकनीक का ट्रायल

प्र. भारत में 5G इंटरनेट तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 5G यानी पाँचवीं जनरेशन सेलुलर सेवा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है।
2. इसे 4G नेटवर्क का अगला वर्जन कहा जा सकता है।
3. इसमें यूजर्स को ज्यादा नेट स्पीड, कम लेटेंसी और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी।
4. 5G की पीक स्पीड 20 GBPS यानी 20 जीबी प्रति सेकेंड तक की होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) उपर्युक्त सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

11. तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया

प्र. हाल ही में चर्चित ग्लाइफोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ग्लाइफोसेट एक खरपतवारनाशी है।
2. इसका IUPAC नाम N-(phosphonomethyl) Glycine है।
3. इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1970 में शुरू किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1, 2 और 3

(D) केवल 2 और 3

Ans: (C)

12. खाद्य मूल्य सूचकांक वर्ष 2014 के बाद से उच्चतम स्तर पर

प्र. खाद्य मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मार्च 2021 की तुलना में अप्रैल 2021 में अनाज के मूल्य सूचकांक में 2% की वृद्धि हुई।
2. पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 26% की वृद्धि हुई है।
3. खाद्य कीमतों में वृद्धि खाद्य मूल्य सूचकांक (Food Price Index) के आधार पर की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

13. वैश्विक मीथेन आकलन

प्र. मीथेन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. मीथेन, ग्रीनहाउस गैस समूह की एक शक्तिशाली गैस है, जोकि पूर्व ख्र औद्योगिक काल से लेकर अब तक हुई तापमान वृद्धि में, 50 प्रतिशत हिस्से के लिये जिम्मेदार है।
2. मीथेन उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा तीन प्रमुख क्षेत्रों जीवाश्म ईंधन: 35%, लैंडफिल और अपशिष्ट: 20% और कृषि: 40% से आता है।
3. मानव गतिविधि द्वारा उत्पन्न मीथेन गैस का बड़ा हिस्सा इन प्रमुख तीन क्षेत्रों से आता है: तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से; विशाल कूड़ा घरों से जहाँ इनसानों द्वारा फेंका गया कूड़ा-कचरा इकट्ठा होता है; और खेतीबाड़ी से- मुख्य रूप से मवेशियों से सम्बन्धित।
4. वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में, मीथेन का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(A) लेवल 2 और 3

(B) केवल 1 और 4

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (B)

14. स्पेसएक्स डॉग -1 मिशन टू द मून

प्र. स्पेसएक्स डॉग -1 मिशन टू द मून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अगले साल यानी 2022 में "DOGE -1 मिशन टू द मून" लॉन्च करेगी।
2. इसका भुगतान कनाडा की कंपनी जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन द्वारा क्रिप्टोकरेंसी डॉगकॉइन (dogecoin) के रूप में किया जाएगा।
3. यह मिशन पृथ्वी की कक्षा से परे क्रिप्टोक्यूरेंसी के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करेगा और इंटरप्लेनेटरी कॉमर्स के लिए नींव स्थापित करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

15. ओसीरिस-रेक्स अंतरिक्षयान (OSIRIS-REx Spacecraft)

प्र. ओसीरिस-रेक्स अंतरिक्षयान (OSIRIS-REx Spacecraft) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. नासा द्वारा फ्लोरिडा के केप केनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से 8 सितंबर, 2016 को अंतरिक्ष यान ओसीरिस-रेक्स (Osiris-REx) का प्रक्षेपण किया गया था।
2. यह अंतरिक्ष यान चाइनीज स्पेस सिस्टम्स द्वारा निर्मित किया गया है।
3. ओसीरिस-रेक्स (Osiris-REx) का पूरा नाम- 'Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Eñplorer' है।
4. यह एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 1, 2 और 4

(C) केवल 1 ,3 और 4

(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (C)

❖❖❖

स्वयं को जाँचें
(विषयनिष्ठ प्रश्न)

01

06

10

01 हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की एक तकनीकी समिति ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (social stock exchange) पर सामाजिक उद्यमों और गैर-लाभकारी संगठनों को शेयर सूचीबद्ध कराने के विस्तृत नियम बनाने के सुझाव दिए हैं। ये सुझाव किस प्रकार इन संगठनों को मजबूती प्रदान करेगी? टिप्पणी कीजिये।

02 हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की समीक्षा कीजिये।

03 हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी- सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट (बंगलुरु) द्वारा 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021: वन ईयर ऑफ कोविड-19' शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

04 ब्लैक फंगस क्या है? यह किस प्रकार लोगों को प्रभावित कर रहा है?

05 5G इंटरनेट तकनीक का ट्रायल क्या है? इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाओं की चर्चा कीजिये।

06 खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation) के अनुसार अप्रैल, 2021 में लगातार 11वें महीने विश्व खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई। इसके क्या कारण है परीक्षण कीजिये।

07 मीथेन उत्सर्जन क्या है? इसके कारणों का परीक्षण करते हुए आवश्यक उपाय भी सुझाएँ।

08 'तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय' (3rd Arctic Science Ministerial-ASM3) बैठक क्या है और यह किस प्रकार भारत के हितों को प्रभावित करता है? चर्चा कीजिये।

09 हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा हटाने का समर्थन किया है। डबल्यूटीओ में पेटेंट संबंधी सुरक्षा से छूट वैश्विक वैक्सीन उत्पादन कितना कारगर होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।

10 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज, आयुष-64 और काबासुरा कुडिनीर मेडिसिन पर टिप्पणी लिखिए।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

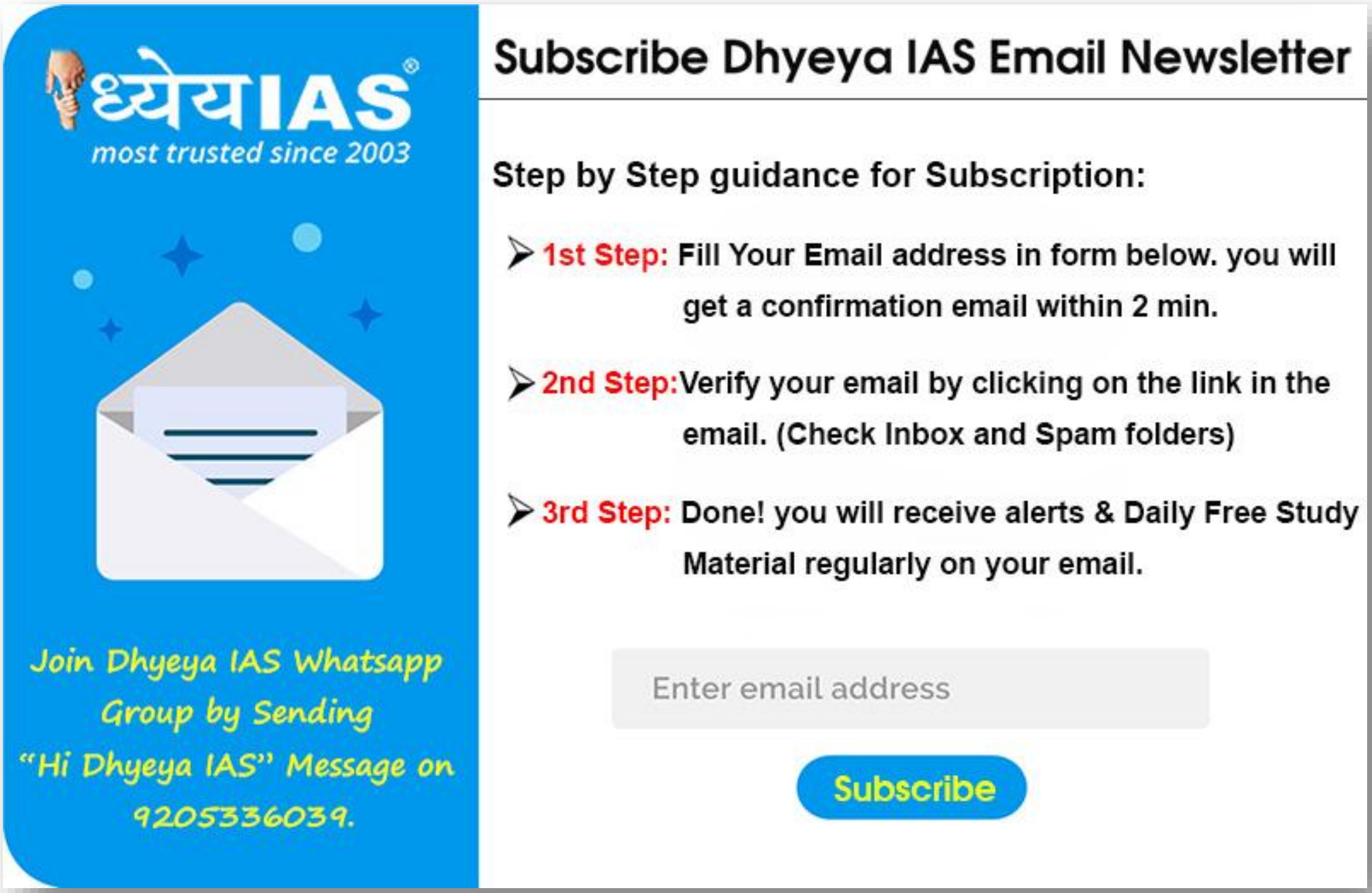

ध्येय IAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com